

[2023] 8 एस. सी. आर 183

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड

बी.

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग

(सीईआरसी) और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील No.11095)

अप्रैल 20,2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.]

बिजली के कलपुर्जों को "परिवर्तन" माना जाएगा

कानून की घटनाएँ-आयोजित: "कानून" शब्द को शक्ति 'कानून' में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ सभी कानूनों सहित होगा।

खरीद समझौते भारत में लागू बिजली कानून और कोई भी कानून, अध्यादेश, विनियम, आदेश, अधिसूचना या संहिता, नियम, या उनमें से किसी की कोई भी व्याख्या भारतीय सरकारी उपकरण द्वारा और

कानून का बल रखने वाले-इसमें सी. ई. आर. सी. और एम. ई. आर. सी. के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश भी शामिल होंगे-इस प्रकार, ऐसे सभी अतिरिक्त शुल्क जो कट-ऑफ तिथि के बाद राज्य के उपकरणों द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, विनियमों आदि के कारण देय हैं, उन्हें 'कानून में परिवर्तन' घटना माना जाएगा-जनरेटर कट-ऑफ तिथि के बाद होने वाले ऐसे परिवर्तनों पर प्रतिस्थापन सिद्धांत पर मुआवजे के हकदार होंगे-'रेलवे बोर्ड' द्वारा समय-समय पर व्यस्त सीजन अधिभार, विकास अधिभार और बंदरगाह भीड़भाड़ शुल्क पर भुगतान किए जाने वाले शुल्कों का संशोधन 'कानून में परिवर्तन' के दायरे में आएगा-जिसके द्वारा अधिसूचनाएं

इसके अलावा, एन. सी. डी. पी. में बदलाव भी 'कानून में बदलाव' के बराबर होगा।

- वन कर के संबंध में, कट-ऑफ तिथि पर वन क्षेत्र में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खदानों से खनन और परिवहन किए गए कोयले पर कोई वन कर लागू नहीं था-पहली बार, वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना के माध्यम से शुल्क लगाया गया था-छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, जो राज्य का एक साधन भी है, 'कानून में बदलाव' होगी-इस संबंध में एपीटीईएल के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है-साथ ही, वन क्षेत्र में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खदानों से खनन और परिवहन किए गए कोयले पर कोई वन कर लागू नहीं था।

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कैप्टिव कोयला ब्लॉक और गो-नो-गो नीति के कारण अत्यधिक देरी-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि एपीटीईएल द्वारा अपनाया गया तर्क विकृत और मनमाना है-सीआईएल द्वारा लगाया गया ईएफसी जो

सी. आई. एल. का परिपत्र भी 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा-उक्त निष्कर्षों के आलोक में, प्रत्येक अपील को स्वतंत्र रूप से माना जाता है, खारिज कर दिया जाता है-विजली अधिनियम, 2003। विजली-वहन लागत-ब्याज अनुदान-आयोजित: एक बार वहन लागत स्वीकृत हो जाने के बाद, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि वहन लागत पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय सरल ब्याज के आधार पर की जानी चाहिए-वहन लागत पर चक्रवृद्धि ब्याज का अनुदान और वह भी 'कानून में परिवर्तन' की घटना की तारीख से ठोस तर्क पर आधारित है-इसका उद्देश्य एक पक्ष को पुनर्स्थापित करना है

जो 'कानून में परिवर्तन' की घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है और इसे अपनी मूल आर्थिक स्थिति में पुनर्स्थापित करता है जैसे कि ऐसी 'कानून में परिवर्तन' की घटना नहीं हुई थी-कानून की सुसंगत स्थिति और विजली खरीद समझौतों में निहित पक्षों के बीच प्रत्यावर्ती सिद्धांतों के अनुप्रयोग और संविदात्मक दायित्वों की गोपनीयता को देखते हुए, लागत वहन करने के संबंध में एपीटीईएल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कोई हस्तक्षेप नहीं करता है-विजली अधिनियम, 2003।

मैदान में-आयोजित: सी. ई. आर. सी., एस. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से युक्त निकाय हैं-इस न्यायालय को तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में तब तक धीमी गति से काम लेना चाहिए जब तक कि वे विकृत, मनमाने और वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता या उनके विपरीत न पाए जाएं-इस न्यायालय में यू/एस. 125 एस में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर ही अनुमति है। 100 सिविल संहिता प्रक्रिया, 1908-इस प्रकार, इस न्यायालय में अपील केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही स्वीकार्य होगी-हालांकि, उन मामलों में भी जहां ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा सुविचारित समवर्ती आदेश पारित किए जाते हैं, उन्हें डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. के साथ-साथ जनरेटरों द्वारा भी चुनौती दी जाती है। मुकदमेबाजी के लंबित होने के कारण, जो इस बैच के कुछ मामलों में 5 साल से अधिक समय से चल रहा है, बकाया का भुगतान न करने पर डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. द्वारा जनरेटरों को भारी वहन लागत का भुगतान करना होगा, जो बदले में, अंतिम उपभोक्ता को सौंप दिया जाएगा।

अनुचित मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है-भारत संघ, जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)

विद्युत मंत्रालय, उत्पादन करने वाली कंपनियों को डिस्कॉम द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं को भारी वहन लागत से बचा जा सके- अनावश्यक और अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया जा सकता है। अनुचित मुकदमेबाजी, जिसकी लागत भी अंतिम उपभोक्ता को दी जाती है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.100।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. पी. पी. ए. एस. में "कानून" शब्द को परिभाषित किया गया है। "कानून" शब्द की परिभाषा का अवलोकन स्पष्ट रूप से होगा।

यह दर्शाता है कि "कानून" शब्द का अर्थ भारत में लागू बिजली कानूनों और किसी भी कानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम, या भारतीय सरकार के साधन द्वारा उनमें से किसी की कोई भी व्याख्या और कानून का बल रखने वाले सभी कानूनों से होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि "कानून" शब्द में किसी भी भारतीय द्वारा लागू सभी नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं भी शामिल होंगी।

सरकारी साधन और इसमें सीईआरसी और एमईआरसी के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश भी शामिल होंगे। सी. आई. एल. भारत सरकार का एक साधन है और जहां तक ईंधन की कीमत का संबंध है, इसके आदेश इसकी सभी सहायक कंपनियों पर बाध्यकारी हैं। कोयले की कीमत में आधार मूल्य, अन्य शुल्क और वैधानिक शुल्क शामिल हैं जो कोयले की डिलीवरी के समय लागू होते हैं। जैसा कि चर्चा की गई है, 'कानून' शब्द में भारतीय सरकार द्वारा जारी किए गए सभी लागू नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं भी शामिल होंगी। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि ऐसे सभी अतिरिक्त शुल्क जो आदेशों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, विनियमों आदि के कारण देय हैं।

कट-ऑफ तिथि के बाद राज्य के उपकरणों को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में माना जाएगा। जनरेटर प्रतिस्थापन सिद्धांत पर मुआवजे के हकदार होंगे। कट-ऑफ तिथि के बाद होने वाले ऐसे परिवर्तनों पर। [पारस 93,94,96-99] [218-C, E-F; 219-E, G-H; 220-A]

एनर्जी बॉचडॉग बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80; जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और एक अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 697 ; महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण

कंपनी लिमिटेड v. अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड

& ओआरएस। 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन 233-पर निर्भर।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. जहाँ तक व्यस्त मौसम अधिभार में वृद्धि का संबंध है,

कोयले के परिवहन पर विकास अधिभार और भारतीय रेलवे द्वारा बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार का संबंध है, ज्ञात एपीटीईएल ने पाया था कि भारतीय रेलवे एक राज्य की साधनता। यह पाया गया है कि व्यस्त मौसम अधिभार, विकास अधिभार और बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार को समय-समय पर परिपत्रों/अधिसूचनाओं के माध्यम से बढ़ाया गया था।

रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएँ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड, भारत सरकार के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ V. मेसर्स ऑब्जर्वर पब्लिकेशंस (पी) लिमिटेड ने रेलवे बोर्ड को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य माना है। इस प्रकार, ज्ञात ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकी कि व्यस्त मौसम अधिभार पर भुगतान किए जाने वाले शुल्कों का संशोधन,

'रेलवे बोर्ड' द्वारा समय-समय पर विकास अधिभार और बंदरगाह भीड़भाड़ शुल्क 'कानून में बदलाव' के दायरे में आएंगे। [पारस 101-103] [220-C-E]

रेलवे बोर्ड, भारत सरकार बनाम। मेसर्स ऑब्जर्वर

प्रकाशन (पी) लिमिटेड (1972) 2 एस. सी. सी. 266: [1972] 3 एससीआर

865 पर भरोसा किया।

3. जहाँ तक कोयले की गुणवत्ता पर एम. ओ. ई. एफ. की अधिसूचना का संबंध है, एम. ओ. ई. एफ. ने 2 जनवरी 2014 की अधिसूचना के माध्यम से, अर्थात्

विशेष कटौती तिथि, अर्थात् 1 जून 2012 के बाद, बिजली परियोजनाओं को 34 प्रतिशत से कम राख सामग्री वाले लाभकारी कोयले का उपयोग करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एम. ओ. ई. एफ. की 11 जुलाई 2012 की अधिसूचना का मसौदा 2 जनवरी 2014 की अंतिम अधिसूचना में समाप्त हुआ। कल्पना के किसी भी विस्तार से, क्या यह कहा जा सकता है कि एम. ओ. ई. एफ. राज्य का एक साधन नहीं है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, एम. ओ. ई. एफ. ने 34 प्रतिशत से कम राख वाले लाभान्वित कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली परियोजनाओं को अनिवार्य कर दिया है। मान लीजिए, कट-ऑफ तिथि से पहले, इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचनाएँ

दिनांक 11 जुलाई 2012 और 2 जनवरी 2014 "कानून में परिवर्तन" के बराबर होगा। इस प्रकार, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है कि यह 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा। [पैरा 104,105] [220-एफ-एच; 221-ए]

4. यह न्यायालय एनर्जी वॉचडॉग के मामले में भी अडानी राजस्थान मामले में और हाल ही में एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम. एपीएमएल और ओआरएस।

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)

यह माना गया है कि एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा। [पैरा 106] [221-सी]

5. जहाँ तक वन कर का संबंध है, अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन से पता चलेगा कि, कट-ऑफ तिथि पर, वहाँ

वन क्षेत्र में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("एस. ई. सी. एल".) खदानों से खनन और परिवहन किए गए कोयले पर कोई वन कर लागू नहीं था। पहली बार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, वन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ पारगमन (वन उत्पाद नियम) 2001 के 53 प्रावधानों के तहत, 7 रुपये प्रति टन की दर से शुल्क लगाया गया था। निर्विवाद रूप से, उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग द्वारा जारी की जाती है, जो राज्य का एक साधन है। इस प्रकार, उस संबंध में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। [पैरा 107] [221-डी-ई]

6. जहाँ तक 'प्रीमियम मूल्य में वृद्धि' का संबंध है,

निर्विवाद रूप से, कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को रद्द करने और उन पर अत्यधिक देरी के कारण 'प्रीमियम में वृद्धि' का भुगतान करना आवश्यक था। गो-नो-गो नीति का लेखा। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान एपीटीईएल द्वारा अपनाया गया तर्क विकृत है और

मनमाना। [पैरा 108] [221-एफ]

7. ई. एफ. सी. को सी. आई. एल. द्वारा 19 दिसंबर 2017 के अपने परिपत्र के माध्यम से लागू किया गया था। सी. आई. एल. राज्य का एक साधन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कट-ऑफ तिथि पर ई. एफ. सी. की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसे केवल 19 दिसंबर 2017 को लागू किया गया है। इस प्रकार, सी. आई. एल. का 19 दिसंबर 2017 का परिपत्र भी 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा। यह भी विवाद में नहीं है कि ई. एफ. सी. को उत्पादकों द्वारा कोयले की डिलीवरी के समय आधार मूल्य, अन्य शुल्कों और वैधानिक शुल्कों का भुगतान करते हुए भुगतान किया गया है। इस प्रकार, उक्त निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। [पारस 109-111] [221-G-H; 222-A]

8. अनुच्छेद 11 का अवलोकन। 4 पी. पी. ए. से पता चलता है कि किसी भी खरीददार द्वारा मासिक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में

देय तिथि के बाद, खरीददार द्वारा प्रत्येक (2023) 8 एस. सी. आर. के लिए देय बकाया राशि पर देय स्टेट बैंक अग्रिम दर (अल्पावधि के लिए एस. बी. ए. आर.) प्रति वर्ष से 2 प्रतिशत अधिक की दर से विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देरी का दिन। पी. पी. ए. का अनुच्छेद 11.8 पूरक बिल के भुगतान से संबंधित है। यह किसी भी पक्ष को उठाने में सक्षम बनाता है

कुछ घटनाओं के कारण भुगतान के लिए दूसरे पक्ष पर पूरक बिल। अनुच्छेद 11.8 का खंड (iii)। 1 पी. पी. ए. का अनुच्छेद 13 में दिए गए 'कानून में परिवर्तन' से संबंधित है। इसके लिए दूसरे पक्ष द्वारा बिल का भुगतान करना आवश्यक है। अनुच्छेद 11.8। 3 पी. पी. ए. का यह भी प्रावधान है कि किसी भी पक्ष द्वारा बिलिंग की तारीख से एक महीने से अधिक समय तक पूरक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में, विलंब भुगतान अधिभार अनुच्छेद 11.3 में मासिक बिल पर लागू होने वाली समान शर्तों पर देय होगा। 4 . उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एन. एच. वी. एन. एल.) के मामले में यह न्यायालय और एक अन्य V. अडानी पावर लिमिटेड और अन्य ने माना है कि जहां तक "संचालन अवधि" का संबंध है, किसी भी वृद्धि के लिए मुआवजा /

विक्रेता के लिए राजस्व या लागत में कमी का निर्धारण और प्रभाव ऐसी तारीख से किया जाना है जो उपयुक्त आयोग द्वारा तय की जाती है। यह आगे कहा गया है कि मुआवजा है

केवल विक्रेता को राजस्व या लागत में वृद्धि/कमी के लिए देय है यदि यह एक अनुबंध वर्ष के लिए कुल मिलाकर ऋण पत्र के 1 प्रतिशत के बराबर राशि से अधिक है। यह माना गया है कि एक निश्चित सीमा के मामले में प्रतिस्थापन सिद्धांत लागू होते हैं

पार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अंतर्निर्मित प्रतिस्थापन सिद्धांत इस तरह के 'कानून में परिवर्तन' से प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति देता है और

वितरण कंपनी लिमिटेड V. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और अन्य, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए चालान का समय पर भुगतान करने के लिए डिस्कॉम का संविदात्मक दायित्व है।

उसी की जांच और सत्यापन के लिए। इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि वित्त पोषण लागत एल. पी. एस. की दर से बहुत कम थी। इस न्यायालय ने इस प्रस्ताव को दोहराया है कि अदालतें पक्षों के बीच निष्पादित किए गए अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती हैं। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं तो वह पक्षों द्वारा वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

यह जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड है। वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षों के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं। पी. पी. ए. का अनुच्छेद 11.8 किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष पर पूरक विधेयक उठाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 13 में दिए गए 'कानून में परिवर्तन' के कारण पक्षकार और ऐसे बिलों का भुगतान किसी भी पक्ष द्वारा किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 11.8। 3 पी. पी. ए. का विशेष रूप से प्रावधान है कि देरी की स्थिति में

बिलिंग की तारीख से एक महीने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा पूरक बिल का भुगतान, अनुच्छेद 11.3 में मासिक बिल पर लागू होने वाली समान शर्तों पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा। 4 . अनुच्छेद 11.3। 4 पी. पी. ए. विशेष रूप से विलंबित भुगतान प्रदान करता है।

विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक आधार पर गणना की गई बकाया भुगतान की राशि (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) पर खरीदार द्वारा विक्रेता को लागू एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष से 2 प्रतिशत अधिक की दर से अधिभार का भुगतान किया जाएगा। उत्तर हरियाणा में बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम। अदानी पावर

(मुंद्रा) लिमिटेड और एक अन्य इस न्यायालय ने दोहराया है कि एक बार वहन लागत स्वीकृत हो जाने के बाद, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि वहन लागत पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय सरल ब्याज के आधार पर की जानी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वहन लागत पर चक्रवृद्धि ब्याज का अनुदान और वह भी इस तिथि से

'कानून में परिवर्तन' घटना की घटना ध्वनि तर्क पर आधारित है। यह माना गया है कि इसका उद्देश्य एक पार्टी को पुनर्स्थापित करना है जो है 'कानून में परिवर्तन' घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होकर इसे अपनी मूल आर्थिक स्थिति में बहाल करें जैसे कि ऐसी 'कानून में परिवर्तन' घटना नहीं हुई हो। इस तर्क को कि पी. पी. ए. में उस तारीख से चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है जब 'कानून में परिवर्तन' की घटना हुई थी, इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है। कानून की इस सुसंगत स्थिति और पुनर्स्थापनात्मक सिद्धांतों के अनुप्रयोग और पी. पी. ए. एस. में निहित पक्षों के बीच संविदात्मक दायित्वों की गोपनीयता को देखते हुए, लागत वहन करने के संबंध में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण।

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पारस 116-126] [223-D-G; 225 B-F; 227-D-H; 228-A; 229-D-G]

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएनएचबीएनएल) और एक अन्य V. अदानी पावर लिमिटेड और अन्य (2019) 5 एससीसी 325: [2019] 4 एससीआर 487; महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वी।

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य (2022) 4 एस. सी. सी. 657; उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम। अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड और एक अन्य (2023) 2 एस. सी. सी. 624-पर निर्भर थे।

9. 2018 की सिविल अपील सं. 11095 और सिविल अपील सं. 11910 - 11911 2018 का

अपीलों के इन समूह में, जहाँ तक अपील की बात है

डी. एन. एच. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. चिंतित है, वे व्यस्त मौसम अधिभार की अनुमति देने वाले विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश से व्यथित हैं और कोयले की गुणवत्ता पर विकास अधिभार, एम. ओ. ई. एफ. अधिसूचना और

एन सी डी पी में परिवर्तन। वे वहन लागत के संबंध में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष से भी व्यथित हैं। जहाँ तक व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार का संबंध है, वे भारत सरकार के परिपत्रों/अधिसूचनाओं के तहत जारी किए जाते हैं।

रेलवे। कोयले की गुणवत्ता पर अधिसूचना एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जारी की जाती है। ये सभी राज्य के साधन हैं, और ये, इसलिए, यह 'कानून में परिवर्तन' के बराबर है। जहाँ तक बाकी दावों का संबंध है, जो दोनों सी. ई. आर. सी. द्वारा समवर्ती रूप से अनुमत और अस्वीकृत हैं

और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल., निर्णयों को देखते हुए चिंतित हैं।

इस मुद्दे पर इस न्यायालय का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी विकृति, मनमानेपन और/या वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन को ध्यान में नहीं रखते हुए, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, जनरेटर और डी. एन. एच.-डिस्कॉम दोनों की अपीलें खारिज की जा सकती हैं। [पारस 132,134,135] [232-जी-एच; 232-ए, बी-डी]

10. सिविल अपील सं। 4628-4629 2021 का

विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने केवल व्यस्त मौसम अधिभार और विकास के आधार पर जनरेटर के दावे की अनुमति दी

कोयले के परिवहन पर अधिभार और वहन लागत। में।

उपरोक्त मुद्दों पर निष्कर्ष निकालने के लिए, उस संबंध में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज किए जाने योग्य हैं।

[पैरा 136,137] [232-ई-एफ]

11. सिविल अपील सं। 12055-12056 2018 का

व्यस्त मौसम अधिभार, विकास का मुद्दा

ऊपर हम पहले ही अधिभार और बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार पर विचार कर चुके हैं। ये सभी शुल्क जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड के तहत हैं।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)

बोर्ड। इस प्रकार, ज्ञात ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष के साथ कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है कि वे 'कानून में परिवर्तन' की घटनाओं के बराबर होंगे। जहाँ तक 'वन कर' लगाने का संबंध है, वही राज्य सरकार द्वारा वैधानिक प्रावधानों के तहत लगाया जाता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है सीखा हुआ ए. पी. टी. ई. एल.। तदनुसार, अपील खारिज किए जाने योग्य हैं। [पैरा 138,139,141] [232-एफ-जी; 233-ए]

12. सिविल अपील सं। 2935-2936 2020 का द्वारा प्रदत्त 'कानून में परिवर्तन' लाभों के अलावा

राज्य आयोग, 'कोयला टर्मिनल अधिभार', 'छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकार' और 'छत्तीसगढ़ विकास उपकार' भी थे।

विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा 'कानून में परिवर्तन' की घटनाएँ मानी जाती हैं। 'कोयला टर्मिनल अधिभार' भारतीय रेलवे द्वारा कट-ऑफ तिथि के बाद लगाया गया था। इसी तरह, छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 जून 2015 की अधिसूचना, जो कि निश्चित रूप से कट-ऑफ तिथि के बाद है, के माध्यम से छत्तीसगढ़ समन्वय विकास एवं पर्यावरण उपकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत 'छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकार' और 'छत्तीसगढ़ विकास उपकार' की शुरुआत की। यहां तक कि संचालन अवधि के लिए सेवा कर पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर में परिवर्तन और संचालन अवधि के लिए सेवा कर पर 5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर में परिवर्तन, जिसे राज्य द्वारा समवर्ती रूप से दिया गया था।

कट-ऑफ तिथि के बाद भारत का। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इन सभी अतिरिक्त करों या उपकरणों को भारत सरकार या द्वारा उपकरणों

छत्तीसगढ़ सरकार। ये संबंधित कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि के प्रावधानों के तहत जारी किए जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे पी. पी. ए. में परिभाषित 'कानून' शब्द के अर्थ के भीतर 'कानून' के बराबर होंगे। इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. के क्रम में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज किए जाने योग्य हैं। [पैरा 142-145] [232-बी-एफ]

13. 2019 की सिविल अपील संख्या 3123 और सिविल अपील No.5372

[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में, सी. ई. आर. सी. द्वारा दिए गए दावों के अलावा, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने निम्नलिखित दावों को भी मंजूरी दी: (i) एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन (कैप्टिव ब्लॉक बनाम टेपरिंग लिंकेज को रद्द करना), (ii) व्यस्त सीजन अधिभार और विकासात्मक अधिभार, (iii) वहन लागत; और (iv) प्रीमियम मूल्य में वृद्धि। जहाँ तक अन्य दावों की बात है जो समवर्ती रूप से अनुमत थे और

सी. ई. आर. सी. द्वारा अस्वीकृत और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. चिंतित हैं, समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दोनों डिस्कांम्स की अपीलों के साथ-साथ

इसलिए उत्पादन करने वाली कंपनियों को बर्खास्त किया जा सकता है।

[पारस 146,151,152] [233-जी-एच; 234-ए, ई-एफ]

14. 2019 की सिविल अपील संख्या 6641

यह अपील जी. के. ई. एल. द्वारा दायर की गई है, जो कुछ घटकों पर लाभों के समवर्ती इनकार से व्यथित है। जैसा कि समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए ऊपर चर्चा की गई है।

सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा अभिलिखित

दावों को अस्वीकार करते हुए, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज की जा सकती है। [पैरा 153,154] [234-एफ-जी]

15. सिविल अपील सं। 5583-5584 2021 का

वर्तमान मामले में, लाभ निम्नलिखित आधारों पर दिया जाता है: (i) एन. सी. डी. पी. में बदलाव के कारण घरेलू कोयले में कमी; (ii) मौजूदा कटौती के कारण प्रीमियम में वृद्धि। तीन साल तक जुड़ाव; (iii) व्यस्त मौसम अधिभार। जहाँ तक व्यस्त मौसम अधिभार का संबंध है, तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों के अलावा, ऊपर पहले से ही कारण दिए गए हैं कि यह 'कानून में परिवर्तन' के बराबर कैसे होगा। अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार, वे ही खारिज किए जाने योग्य हैं। [पारस 155,157,158] [234-एच; 235-ए-सी]

16. 2021 की सिविल अपील संख्या 39

सी. ई. आर. सी. ने निम्नलिखित आधारों पर लाभ प्रदान किया है: आई.

एन. सी. डी. पी. 2013 और शक्ति नीति के कारण लिंकेज कोयले में कमी; पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के संशोधन के अनुसार कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन; जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड के परिवहन पर व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार में वृद्धि।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)

भारतीय रेलवे द्वारा कोयले का उत्पादन; और iv. अनुमत 'कानून में परिवर्तन' दावों पर लागत वहन करना। सी. ई. आर. सी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा की गई है। इस प्रकार, अपील तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों से उत्पन्न होती है। अन्य घटक, अर्थात् पर्यावरण संशोधन के अनुसार कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन।

(संरक्षण) नियम, 1986 और भारतीय रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन पर व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार में वृद्धि, हम पहले ही इसमें 'कानून में परिवर्तन' की घटनाओं के बराबर मान चुके हैं। 'वहन लागत' के मुद्दे पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए। अपील, तदनुसार है, बर्खास्त किया जा सकता है। [पैरा 159,160,163] [235-डी-एफ; 236-बी-सी]

17. 2022 की सिविल अपील सं. 5005 और सिविल अपील सं.

' वहन लागत '। निर्विवाद रूप से, ई. एफ. सी. को सी. आई. एल. द्वारा 19 दिसंबर 2017 के अपने परिपत्र के माध्यम से लागू किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि ई. एफ. सी. का भुगतान जेनरेटरों द्वारा आधार मूल्य, अन्य शुल्कों और वितरण के समय वैधानिक शुल्कों का भुगतान करते हुए किया गया है। कोयला। इस प्रकार, उक्त निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक 'वहन लागत' का संबंध है, इसलिए उक्त मुद्दे पर भी कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार, वे ही खारिज किए जाने योग्य हैं। [पारस 164-168] [236-डी-एफ]

18.1 सी. ई. आर. सी., एस. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से बने निकाय हैं। वर्तमान में कई अपीलें

समूह इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो वैधानिक निकायों द्वारा प्राप्त तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों से उत्पन्न होता है। कुछ मामलों में, अपील केवल इसे दायर करने के लिए दायर की गई हैं। कुछ कार्यवाहियों में मुकदमे के कई दौर हो चुके हैं। हाल ही में, यह न्यायालय, एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामले में। एपीएमएल और ओआरएस। उन्होंने कहा है कि विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने का एक कारण यह था कि विभिन्न कारकों के कारण विद्युत बोर्डों का प्रदर्शन बिगड़ गया था। द. विद्युत अधिनियम, 2003 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलेगा कि [2023] 8 एस. सी. आर. के अधिनियमन के लिए मुख्य विशेषताओं में से एक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम उत्पादन को अलग करने और स्वतंत्र रूप से कैप्टिव उत्पादन की अनुमति देने वाला था। उक्त निर्णय में, एनर्जी वॉचडॉग के मामले में विद्वान अटॉर्नी जनरल का बयान दर्ज किया गया कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने के बाद, बिजली अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को काफी हद तक पूरा किया गया था। उन्होंने कहा था कि कम बिजली उत्पादन के परिणामस्वरूप पहले की तुलना में कहीं अधिक बिजली का उत्पादन हुआ था। विद्वान महान्यायवादी ने न्यायालय से बिजली अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले नाजुक संतुलन को बाधित नहीं करने का आग्रह किया था, यानी कि बिजली के उत्पादक या जनरेटर, ताकि वे बिजली संयंत्र स्थापित कर सकें, लाभ के उचित अंतर और उनके लाभ पर उचित प्रतिफल के हकदार हों।

पूँजी, ताकि वे अधिक से अधिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित हों। साथ ही अंतिम उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करने की आवश्यकता है। हालाँकि, इस स्थिति के बावजूद, मुकदमों के बाद मुकदमों को आगे बढ़ाया जाता है। यद्यपि समवर्ती आदेश

वैधानिक विशेषज्ञ निकायों को विकृत, मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में, उन्हें चुनौती दी जाती है। यहां तक कि संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि 'कानून में बदलाव' की स्थिति से उत्पन्न आदेशों के संबंध में एकरूपता और एकरूपता होनी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि नियामकों के आदेशों को उनके लिए विद्वान ए. पी. टी. ई. एल./उच्च न्यायपालिका के पास ले जाने की स्थिति में डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. द्वारा भुगतान किए जाने वाले नियामक बकाया के निश्चित प्रतिशत के लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए। विचार और निर्णय। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के संदर्भ में बिजली मंत्रालय द्वारा सी. ई. आर. सी. को जारी 27 अगस्त 2018 के नीतिगत निर्देश का भी उल्लेख किया है, जिसमें उसने शीघ्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की वसूली। सीखा हुआ ए. पी. टी. ई. एल. 22 अक्टूबर 2021 को बिजली मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बिजली (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें मुआवजे की समय पर वसूली का प्रावधान है

'कानून में परिवर्तन' की घटनाओं के कारण। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने पाया कि हरियाणा उपयोगिताएँ अपना रही हैं।

विलम्बकारी रणनीतियाँ, जो न केवल सार्वजनिक नीति को पराजित करती हैं, बल्कि अंत में जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड के बोझ को बढ़ाने के अवांछनीय परिणाम भी हैं।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)

वे उपभोक्ता बढ़ती हुई 'वहन लागत' के कारण सेवा करने का दावा करते हैं। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने आगे पाया कि करें और शुल्कों सहित पिछले भुगतानों को रोकना

डिस्कॉम्स द्वारा, पी. पी. ए. के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो विवाद की परवाह किए बिना उठाए गए चालान का सम्मान करने के लिए खरीदार पर एक विशिष्ट जनादेश देता है, और एक विशिष्ट आदेश लागू करता है।

एकतरफा कटौती/सेटिंग ऑफ के खिलाफ प्रतिबंध। 'कानून में परिवर्तन' की घटनाएं उस तारीख से आनी होंगी जिस दिन राज्य की संस्थाओं द्वारा नियम, आदेश, अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। इस निष्कर्ष के बावजूद, डिस्कॉम मुकदमेबाजी के बाद मुकदमेबाजी कर रहे हैं। जब पी. पी. ए. स्वयं 'कानून में परिवर्तन' के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, तो अनुचित मुकदमेबाजी, जो न्यायालय का समय बर्बाद करती है और साथ ही अंतिम उपभोक्ता द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की अंतिम लागत में वृद्धि करती है, से बचा जाना चाहिए। अंततः, डिस्कॉम्स के साथ-साथ जनरेटरों की ओर से मुकदमेबाजी की भारी लागत बढ़ जाती है

बिजली की लागत जो अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है। [पैरा 128,169,174-176] [230-A; 237-A-E; 240-C-G; 241-A-C]

18.2 यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय में अपील

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत केवल संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर अनुमति है। सिविल प्रक्रिया, 1908। इस प्रकार, इस न्यायालय में अपील केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही स्वीकार्य होगी। हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले ही देखा गया है, उन मामलों में भी जहाँ विद्युत नियामक आयोगों और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा सुविचारित समवर्ती आदेश पारित किए जाते हैं, उन्हें चुनौती दी जाती है

मुकदमेबाजी की विचाराधीनता, जो इस बैच के कुछ मामलों में 5 साल से अधिक समय हो गया है, बकाया का भुगतान न करने पर डिस्कॉम्स द्वारा जनरेटरों को भारी वहन लागत का भुगतान करना होगा, जो बदले में अंतिम उपभोक्ता को दिया जाएगा। नतीजतन, यह अंतिम उपभोक्ता होगा जो पीड़ित होगा। इस तरह के अनावश्यक और अनुचित मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

[पैरा179] [241-ई-एच]

18.3 इसलिए विद्युत मंत्रालय ("एमओपी") के माध्यम से भारत संघ से एक तंत्र विकसित करने की अपील की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

उत्पादन करने वाली कंपनियों को डिस्कॉम द्वारा समय पर भुगतान, [2023] 8 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो भारी बहन लागत को पार करने से बचाएगा

अंतिम उपभोक्ता। भारत संघ, एमओपी के माध्यम से, अनावश्यक और अनुचित मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है, जिसकी लागत भी अंतिम उपभोक्ता को दी जाती है। [पारस 181,182] [242-बी-सी]

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी

सीमित वी। जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड और अन्य। सिविल अपील

2021 का सं. 6927; मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रिंसिपल

सचिव और अन्य। (2014) 9 एससीसी 516: [2014] 8 एससीआर

446 ; और 2014 (9) एससीसी 614: [2014] 12 एससीआर 110;

अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम।

भारत संघ और अन्य (2007) 2 एस. सी. सी. 640: [2006]

9 पूरक। एस. सी. आर. 954; उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

सीमित और एक अन्य वी। अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड

और 2021 की एक अन्य सिविल अपील संख्या 5684;

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी

सीमित वी। अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और

एक अन्य सिविल अपील सं। 677- 678 2021 का-संदर्भित
को।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 8 एससीआर 446

पैरा 73

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 110

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[2006] 9 पूरक। एससीआर 954

संदर्भित किया गया है

पैरा 90

[1972] 3 एससीआर 865

उस पर भरोसा करें

पैरा 102

[2019] 4 एससीआर 487

उस पर भरोसा करें

पैरा

117,17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1

2018 से।

ऐप के 14.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की अपील No.111 में नई दिल्ली में विद्युत न्यायाधिकरण।

के साथ

सिविल अपील सं। 11910-11911 , 12055-12056 2018 का 3123,

6641 2019 का, 2020 का 2935-2936,4628-4629,5583-5584,25005 का
39,2022 का GMR वारोरा एनर्जी लिमिटेड का 4089।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., जी. साईकुमार, समीर मलिक, सुश्री निकिता चौकसे,

आकाश लांबा, नमन टंडन, सुश्री फरहा मलिक, चंद्र प्रकाश, सुश्री स्वप्ना सिन्हा, मेसर्स डी. एस. के. लीगल, अनूप जैन, उदित गुप्ता, राघवेंद्र प्रताप सिंह, मेसर्स उदित किशन एंड एसोसिएट्स, शुभम आर्य, सुश्री पूर्वा सहगल, निकुंज दयाल, सुश्री पल्लवी सहगल, सुश्री शिखा सूद, सुश्री रीहा सिंह, सुश्री अनुमेहा स्मिटी, रवि नायर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल,

सुश्री पूनम सेनगुप्ता, अर्शित आनंद, सौनक राजगुरु, निधिराम शर्मा, सुश्री निधिराम शर्मा, सुश्री साक्षी कपूर, ई. सी. अग्रवाल, विश्व मुखर्जी, पुखरंभ रमेश कुमार, गिरिक भल्ला, करुण शर्मा, सुश्री प्रियंका व्यास, सूरज दासगुरु, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

सूचकांक *

आई.

परिचय।

पैरा 1 से 5

II. संक्षिप्त तथ्य और प्रस्तुतियाँ..

पैरा 6 से 91 तक

... पैरा 92

III. अतिरिक्त मुद्दे।

पारस 93 से 130

IV. समन्वय।

131 से 168

V. निष्कर्ष।

.....

पै

.

.....

. पारस

VI. एपिलॉग।

. पारस

169 से 184

संक्षिप्त नामों की सूची:

विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

1 .

एपीटीईएल

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

2 .

सी. ई. ए

केंद्रीय विद्युत नियामक

3 .

सीईआरसी

आयोग

4 .

सीआईएल

कोल इंडिया लिमिटेड

वाणिज्यिक संचालन तिथि

सीओडी

5 .

कोयला आपूर्ति समझौता

6 .

सीएसए

वितरण कंपनियाँ

7 .

डिस्कॉम

- ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

8 .

ई. सी. एल.

* एड नोट: सूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

सी आरा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निकासी सुविधा शुल्क

9 .

ई. एफ. सी.

10 .

एफएसए

ईंधन आपूर्ति समझौता

11. जीसीवी

सकल कैलोरी मूल्य

12. एलओए

आश्वासन पत्र

13. एलपीएस

विलंबित भुगतान अधिभार

14. एमएटी

न्यूनतम वैकल्पिक कर

महानदी कोलफील्ड लिमिटेड

15 .

एमसीएल

महाराष्ट्र विद्युत नियामक

16. एमईआरसी

आई.

आयोग

कोयला मंत्रालय

17. एमओसी

विद्युत मंत्रालय

18 .

एमओपी

महाराष्ट्र राज्य बिजली

19 .

एमएसईडीसीएल

1

वितरण कंपनी लिमिटेड

20 .

नई कोयला वितरण नीति

एनसीडीपी

बिजली खरीद समझौते

21. पीपीएस 22 .

आरएफपी

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

23. एसबीएआर

स्टेट बैंक अग्रिम दर

साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड

24. एसईसीएल

उपयोग और उपयोग के लिए योजना

25. शक्ति

कोयले का आवंटन भारत में पारदर्शी रूप से

26 .

एसएचआर

स्टेशन गर्मी दर

टैंगेडको -

27 .

तमिलनाडु उत्पादन और वितरण
निगम

28. यूएचवी

उपयोगी ऊष्मा मूल्य

I. परिचय

1. जब हमने बिजली की अपीलों के इस समूह को सुना, तो इस पर सहमति बनी

सभी पक्षों का कहना है कि इस न्यायालय को पहले 2021 की सिविल अपील 584 (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण) पर निर्णय लेना चाहिए। पैनी लिमिटेड वी। अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड & Ors.¹⁾

ईडीसीएल V. ए. पी. एम. एल. और अन्य "। संक्षेप में] और सिविल अपील सं. 6927

एससीसी ऑनलाइन 233 जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड। वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

2021 (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम। जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड) , चूंकि समूह की सभी अपीलों में शामिल तीन मुद्दे समान थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि उन दोनों अपीलों का निर्णय तीन सामान्य मुद्दों पर निर्णय लेकर किया जा सकता है। हालांकि, जहां तक अन्य अपीलों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि तीन सामान्य मुद्दों के अलावा, कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी शामिल थे और यह सहमति हुई कि उन दो अपीलों पर निर्णय लेने के बाद, इन अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए अन्य अपीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।

2. उक्त तीन सामान्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

क्या नए कोयले के कारण 'कानून में बदलाव' से राहत मिलेगी

(i)

वितरण नीति, 2013 (संक्षेप में "एन. सी. डी. पी. 2013") "वास्तविक" पर होनी चाहिए। नई कोयला वितरण नीति, 2007 (संक्षेप में "एन. सी. डी. पी. 2007") के संदर्भ में मानक कोयले की आवश्यकता के 100% की तुलना में या

एन. सी. डी. पी. 2013 में ट्रिगर स्तर। 65 % , 65 % , 67 % और 75 प्रतिशत

ए. सी. क्यू?

((ख)

चाहे 'कानून में परिवर्तन' राहत की गणना के लिए,

परिचालन मापदंडों पर 'वास्तविक' या बोली में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी के अनुसार विचार किया जाना चाहिए?

(iii)

क्या 'कानून में परिवर्तन' राहत मुआवजा होना है

1 अप्रैल 2013 (वित्तीय वर्ष की शुरुआत) या 31 तारीख से दिया गया

जुलाई 2013 (एन. सी. डी. पी 2013 की तिथि)?

3. पक्षों के लिए सभी विद्वान वकीलों को व्यापक रूप से सुनने के बाद, एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामले में 3 मार्च 2023 के निर्णय और आदेश को देखें। एपीएमएल और ओआरएस। (ऊपर), इस न्यायालय ने उपरोक्त तीन मुद्दों पर विचार करने के बाद उन दो अपीलों का फैसला किया।

4. इस न्यायालय द्वारा पहले मुद्दे का उत्तर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि

'घरेलू कोयले की कमी के लिए कानून में बदलाव 'राहत' 'वास्तविक' पर होनी चाहिए, यानी एन. सी. डी. पी., 2007 के संदर्भ में आश्वासन दी गई मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के विपरीत। जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह माना गया कि स्टेशन गर्मी दर (संक्षेप में "एसएचआर") और सहायक खपत विनियमों या वास्तविक नियमों के अनुसार, जो भी कम हो, उस पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरे मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया गया कि एन. सी. डी. पी., 2013 के लिए 'कानून में बदलाव' कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख 1 अप्रैल 2013 है।

5. उन अपीलों पर निर्णय लेने के बाद, हमने वर्तमान पर सुनवाई की है

अपील जिसमें कुछ मुद्दे जो हमारे द्वारा [2023] 8 एस. सी. आर. के माध्यम से तय किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामले में कहा गया निर्णय। एपीएमएल और ओआरएस। (उपर्युक्त) अन्य मुद्दों के साथ विचार के लिए भी उभरा। हालाँकि, इन सभी अपीलों में अधिकांश मुद्दे अतिव्यापी हैं और इसलिए, हम इन अपीलों पर इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं।

II. संक्षिप्त तथ्य और प्रस्तुतियाँ

2018 की सिविल अपील सं. 11095 और सिविल अपील सं. 11910 11911 2018 का 6. ये परस्पर अपीलें विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 14 अगस्त 2018 के सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं।

7. 2018 की सिविल अपील जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "जी. डब्ल्यू. ई. एल."/ "जनरेटर" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा इस हद तक दायर की गई है कि इसे "कानून में परिवर्तन" के आधार पर कुछ घटकों पर प्रतिपूरक लाभों से वंचित कर दिया गया था। 8. सिविल अपील सं। 11910-11911 डी. एन. एच. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (डी. पी. डी. सी. एल.) (इसके बाद डी. एन. एच. के रूप में संदर्भित) द्वारा 2018 का आवेदन दायर किया गया है।

डिस्कॉम), कुछ मुद्दों पर जी. डब्ल्यू. ई. एल. के दावे को स्वीकार करने वाले विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश से व्यथित है और इसे 'कानून में परिवर्तन' मानता है।

9. संक्षेप में, इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

10. जी. डब्ल्यू. ई. एल. ने महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के वरोरा में एक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया था, जिसकी स्थापित क्षमता

600 मेगावाट (2 x 300 मेगावाट)। इकाई 1 की वाणिज्यिक संचालन तिथि (संक्षेप में "सीओडी") 19 मार्च 2013 थी और इकाई 2 की 1 सितंबर 2013 थी।

11. जी. डब्ल्यू. ई. एल. ने दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते किए थे।

(" महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए डी. एन. एच.-डिस्कॉम के साथ पी. पी. ए. "संक्षेप में)

(" एम. एस. ई. डी. सी. एल./डी. एन. एच.-डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरने के बाद, 17 मार्च 2010 को एम. एस. ई. डी. सी. एल. पी. पी. ए.) और 21 मार्च 2013 को 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए (डी. एन. एच. पी. पी. ए.)। एम. एस. ई. डी. सी. एल. पी. पी. ए. के तहत अनुसूचित वितरण तिथि 17 मार्च 2014 थी, जबकि डी. एन. एच. पी. पी. ए. के तहत यह 1 अप्रैल 2013 थी। जी. डब्ल्यू. ई. एल. अपने बिजली संयंत्र से जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड को 150 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भी कर रहा है।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम ("टैंगेडको") संक्षेप में) व्यापारिक कंपनी के साथ एक के बाद एक व्यवस्था के माध्यम से

जी. एम. आर. एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसके लिए 27 नवंबर 2013 ("टैंगेडको पी. पी. ए.") को एक पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर किए गए थे।

12. पी. पी. ए. एस. के संदर्भ में, कट-ऑफ तिथि, जो 7 दिन पहले है

'कानून में परिवर्तन' के तहत दावों के उद्देश्य के लिए बोली की समय सीमा पर विचार किया जाना है। उक्त पी. पी. ए. के तहत कट-ऑफ तिथियां निम्नलिखित हैं।

एमएसईडीसीएल पीपीए

टैंगेडको

पीपीए

डीएनएच पीपीए

कट-ऑफ तिथि

1.6.2012

31.7.2009

2

7.2.2013

13. इस संबंध में कुछ 'कानून में परिवर्तन' की घटनाएँ हुई

एम. एस. ई. डी. सी. एल. पी. पी. ए. और डी. एन. एच. पी. पी. ए. कट-ऑफ तिथि के बाद। ऐसे ही थे। जी. डब्ल्यू. ई. एल. द्वारा एम. एस. ई. डी. सी. एल./डी. एन. एच.-डिस्कॉम को सूचित किया गया।

14. जी. डब्ल्यू. ई. एल. ने केंद्र के समक्ष याचिका संख्या 8/एम. पी./2014 दायर की

विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद "सी. ई. आर. सी". के रूप में संदर्भित) 'कानून में परिवर्तन' के लिए राहत मांग रहा है।

15. 1 फरवरी 2017 के आदेश के अनुसार, कुछ दावे थे -

सी. ई. आर. सी. द्वारा अनुमति दी गई और कुछ दावों को अस्वीकार कर दिया गया।

16. सी. ई. आर. सी. द्वारा जिन दावों की अनुमति दी गई थी वे इस प्रकार हैं:

" सी. वी. डी. को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना।

ii. उत्पाद शुल्क में वृद्धि;

सेवा कर में वृद्धि;

iii.

अन्य करों में वृद्धि [कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यू. सी. टी.),

iv.

वैट, सीएसटी];

कोयले पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन;

वी.

कोयले पर रॉयल्टी की दर में वृद्धि;

vi.

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा उपकर का शुल्क

vii.

(गोल);

माल के परिवहन पर सेवा कर में वृद्धि

viii.

आईआर;

स्वच्छ भारत उपकर का शुल्क "।

ix.

17. सी. ई. आर. सी. द्वारा अस्वीकार किए गए दावे इस प्रकार हैं:

" 1. डी. जी. एफ. टी. द्वारा मानित निर्यात लाभ की वापसी;

कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) में डिजाइन परिवर्तन;

ii.

न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर में वृद्धि

iii.

टी); [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यस्त मौसम अधिभार और विकास में वृद्धि

iv.

भारतीय द्वारा कोयले के परिवहन पर अधिभार

रेलवे (आईआर);

आकार शुल्क और सतह परिवहन में वृद्धि

वी.

कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) द्वारा शुल्क;

विनिर्देशन के कारण परिचालन लागत में वृद्धि

vi.

टी. पी. एस. के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता;

कोयले के यू. एच. वी. से जी. सी. वी. आधारित मूल्य निर्धारण में परिवर्तन;

vii.

कार्यशील पूंजी पर व्याज में वृद्धि

viii.

(आई. डब्ल्यू. सी.) परियोजना लागत में वृद्धि के कारण।

18. द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होना

सी. ई. आर. सी., क्रॉस-अपील जी. डब्ल्यू. ई. एल. और डी. एन. एच.-डिस्कॉम दोनों द्वारा दायर की गई थी।

19. विवादित फैसले के दौरान, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल., जबकि

सी. ई. आर. सी. द्वारा अनुमत दावों पर सी. ई. आर. सी. के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, निम्नलिखित पर 'कानून में परिवर्तन' के आधार पर दावों की अनुमति दी गई: घटक:

(1)

व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार;

((ख)

पर्यावरण और वन मंत्रालय ("एमओईएफ") अधिसूचना

कोयले की गुणवत्ता पर; और

(iii) एन. सी. डी. पी. और वहन लागत में परिवर्तन।

20. हालाँकि, बाकी दावों को सी. ई. आर. सी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जहाँ तक

डी. एन. एच.-डिस्कॉम द्वारा दायर अपील का संबंध है, इसे विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, ये परस्पर विरोधी अपीलें हैं।

21. हमने विद्वान वकील श्री विश्रव मुखर्जी को सुना है।

जी. डब्ल्यू. ई. एल. और श्री समीर मलिक की ओर से पेश हुए, एम. एस. ई. डी. सी. एल. और श्री एम. जी. रामचंद्रन की ओर से पेश हुए विद्वान वकील, डी. एन. एच.-डिस्कॉम की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील।

22. श्री विश्व मुखर्जी प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने

निम्नलिखित वस्तुओं पर दावे को अस्वीकार करने में त्रुटि हुई: (i) 28 दिसंबर 2011 के परिपत्र और विदेश व्यापार महानिदेशालय ("डीजीएफटी") द्वारा 28 दिसंबर 2011 को जारी अधिसूचना के माध्यम से मानित निर्यात लाभ की वापसी और 21 मार्च 2012 की विदेश व्यापार नीति में संशोधन;

(11) क्रशिंग/साइजिंग चार्ज और सतह का अधिरोपण

15 अक्टूबर की अधिसूचना द्वारा परिवहन शुल्क

2009 ; जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

(iii) कोल इंडिया द्वारा कोयले के वर्गीकरण की प्रणाली में परिवर्तन।

30 दिसंबर 2011 की अधिसूचना के माध्यम से मूल्य निर्धारण की उपयोगी ऊष्मा मूल्य (संक्षिप्त में "यूएचवी") से सकल ऊष्मा मूल्य (संक्षिप्त में "जीसीवी") प्रणाली तक सीमित (संक्षिप्त में "सीआईएल");

(iv) न्यूनतम वैकल्पिक कर ("एमएटी") के शुल्क में वृद्धि।

लघु) की धारा 115 जेबी के संशोधन के अनुसार

आय कर अधिनियम, 2012;

पत्र के संदर्भ में कोयला हैंडलिंग संयंत्र में डिजाइन परिवर्तन

(v)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (संक्षेप में सी. ई. ए.) द्वारा जारी किया गया

दिनांक 19 अप्रैल 2011;

(vi) कार्यशील पूंजी में वृद्धि।

23. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये सभी परिवर्तन हुए हैं

द्वारा जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों का लेखा-जोखा

राज्य के उपकरणों और इस तरह, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. को उपरोक्त मदों पर भी 'कानून में परिवर्तन' के कारण मुआवजे के दावे की अनुमति देनी चाहिए थी।

24. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'कानून में परिवर्तन' के कारण मुआवजा पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर आधारित है ताकि पक्ष को वापस रखा जा सके।

जिस आर्थिक स्थिति में यह था, क्या 'कानून में परिवर्तन' की घटना नहीं हुई थी। हालाँकि, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा इसे सही परिप्रेक्ष्य में नहीं माना गया है।

25. डी. एन. एच.-डिस्कॉम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

इसके विपरीत, और एम. एस. ई. डी. सी. एल. का कहना है कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार, कोयले की गुणवत्ता पर एम. ओ. ई. एफ. अधिसूचना, एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन और वहन लागत को 'कानून में परिवर्तन' घटनाओं के रूप में मानने में गलती की है। वह प्रस्तुत करता है कि जब

जनरेटर ने अपनी बोली जमा कर दी थी, यह पता था कि कुछ भुगतानों में बदलाव की संभावना थी और बोली जमा करते समय उन्हें शामिल किया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने उक्त मुद्दों पर 'कानून में परिवर्तन' लाभ देने में गलती की।

सिविल अपील सं। 4628-4629 2021 का

26. ये अपीलें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण द्वारा दायर की गई हैं।

निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (इसके बाद "हरियाणा डिस्कॉम" के रूप में संदर्भित) ने 2017 की अपील No.158 और 2018 की आई. ए. No.575 और 2017 की अपील संख्या 316 में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित 7 जून 2021 के सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती दी। 2017 की अपील No.158 और 2018 की I. A. No.575 द्वारा दायर की गई थी

अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड (इसके बाद एपी (एम) एल के रूप में संदर्भित), [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ई. आर. सी. द्वारा 6 फरवरी 2017 को पारित आदेश से व्यथित होने के कारण, जिसमें सी. ई. आर. सी. ने 'कानून में परिवर्तन' के कारण कुछ घटकों पर मुआवजे के लिए कुछ दावों को अस्वीकार कर दिया था, जबकि 2017 की अपील हरियाणा डिस्कॉम द्वारा दायर की गई थी। "कानून में परिवर्तन" के आधार पर कुछ घटकों पर मुआवजे का दावा।

27. दावों का चार्ट जिसकी अनुमति दी गई थी और जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी

सीईआरसी निम्नानुसार है:

" 107. उपरोक्त विश्लेषण और निर्णयों के आधार पर,

परिचालन अवधि के दौरान कानून में परिवर्तन के तहत हमारा निर्णय परियोजना का विवरण इस प्रकार है:

घटकों

में

परिवर्तन करें

कानूनी

घटना

रॉयल्टी की दर में परिवर्तन

अनु

मति दी गई।

में दिए गए निर्देशों के अधीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क का शुल्क

अनु

मति दी गई।

आदेश का पैरा 32

स्वच्छ ऊर्जा उपकरण का शुल्क

अनु

मति दी गई।

एस. ई. जेड. से ऊर्जा पर सीमा शुल्क हटाया गया

अनु

मति दी गई।

डीटीए के लिए

व्यस्त मौसम में परिवहन पर अधिभार में वृद्धि	अनुमति
नहीं है	
कोयला	
परिवहन पर विकास अधिभार में वृद्धि	अनुमति
नहीं है	
कोयले का	कोयले के परिवहन पर सेवा कर
मति दी गई।	अनु
गुजरात में हरित ऊर्जा उपकर का शुल्क	
प्रदान की गई	स्वतंत्रता
बाद दृष्टिकोण	माननीय के
कोर्ट का	सुप्रीम
य	निर्ण
कोयले के आकार शुल्क में वृद्धि	
नहीं है	अनुमति
सतह परिवहन में वृद्धि	
नहीं है	अनुमति
कोयले के मूल्य निर्धारण में यूएचवी से जीसीवी आधार पर परिवर्तन	
नहीं है	अनुमति
रेलवे माल दुलाई के लिए श्रेणी को 140 से 150 में बदला गया	
नहीं है	अनुमति

रेल परिवहन के लिए कोयले के लिए	
में स्थित संयंत्रों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर का शुल्क	
नहीं है	अनुमति
एसईजेड	
रेलवे शुल्क संशोधन को लागत में उतार-चढ़ाव से जोड़ना	
नहीं है	अनुमति
ईंधन का	स्वच्छ भारत उपकर का अधिरोपण
मति दी गई।	अनु
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को भुगतान	
मति दी गई।	अनु
जिला खनिज फाउंडेशन को भुगतान	
मति दी गई।	अनु
पर्यावरण मंजूरी के अनुसार एफ. जी. डी. की स्थापना	
दिनांकित 20.5.2010	
नहीं हुआ।	तय
स्वतंत्रता	और
एफ. जी. डी. स्थापना के कारण सहायक खपत	
क्षमता शुल्क को प्रभावित करना	
दान किया गया	प्र
एफ. जी. डी. पर अतिरिक्त परिचालन व्यय	
वहन लागत	

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड को अनुमति नहीं है। वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

28. सी. ई. आर. सी. के आदेश से व्यथित होकर, ए. पी. (एम) एल. द्वारा और हरियाणा डिस्कॉम द्वारा भी ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष परस्पर अपील दायर की गई थी। हरियाणा डिस्कॉम ने सी. ई. आर. सी. के आदेश के उस हिस्से को चुनौती दी, जिसमें घटकों पर दावे की अनुमति दी गई थी। कानून', जबकि एपी (एम) एल ने सीईआरसी के आदेश के उस हिस्से को चुनौती दी, जिसने विभिन्न घटकों पर अपने दावे को अस्वीकार कर दिया।

29. हालांकि एपी (एम) एल ने विभिन्न घटकों पर 'कानून में बदलाव' मुआवजे की मांग की थी, लेकिन विद्वान एपीटीईएल ने इसकी अनुमति दी थी

केवल इस आधार पर आक्षेपित आदेश द्वारा:

(i) 'व्यस्त मौसम अधिभार और विकासात्मक अधिभार'

कोयले का परिवहन और

((ii) 'वहन लागत'।

30. ए. पी. टी. ई. एल. ने सी. ई. आर. सी. द्वारा लिए गए विचार से सहमति जताते हुए सतह परिवहन शुल्क में वृद्धि और कोयले के आकार शुल्क से संबंधित ए. पी. (एम) एल. के दावे को अस्वीकार कर दिया।

31. सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा कुछ घटकों पर 'कानून में परिवर्तन' की अनुमति देने वाले आदेशों से व्यथित होकर,

हरियाणा डिस्कॉम ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

32. हमने हरियाणा डिस्कॉम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री पूर्वा सहगल और विद्वान वरिष्ठ डॉ. ए. एम. सिंघवी को सुना है। एपी (एम) एल की ओर से पेश वकील।

33. सुश्री पूर्वा सहगल प्रस्तुत करती हैं कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल.

व्यस्त मौसम अधिभार और विकासात्मक अधिभार के मुद्दे पर सी. ई. आर. सी. के सुविचारित निष्कर्षों को उलटने में गलती कोयले का परिवहन। इसलिए वह प्रस्तुत करती है कि उसी के संबंध में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष को अलग रखने की आवश्यकता है।

34. डॉ. ए. एम. सिंघवी, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि व्यस्त मौसम अधिभार के साथ-साथ विकासात्मक अधिभार को संशोधित किया जाता है।

रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएँ/परिपत्र और इस प्रकार, वे 'कानून में परिवर्तन' की परिभाषा के भीतर आएंगे।

सिविल अपील सं। 12055-12056 2018 का

35. ये अपीलें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दायर की गई हैं।

(इसके बाद "राजस्थान डिस्कॉम" के रूप में संदर्भित), विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. [2023] 8 एस. सी. आर. द्वारा पारित 14 अगस्त 2018 के सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2016 की अपील सं. 119 और आई. ए. सं. 668 और 2016 की 674 और 2016 की अपील No.277 और 2016 की आई. ए. No.572 में।

36. 2016 की अपील सं. 119 और आई. ए. सं. 668 & 674 2016 का मामला मेसर्स अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (संक्षेप में "एपीआरएल") द्वारा दायर किया गया था।

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (जिसे इसके बाद "राज्य आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 15 मार्च 2016 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर 'कानून में परिवर्तन' के कारण इसके कुछ दावों को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि 2016 की अपील संख्या 277 और 2016 की आई. ए. No.572 राजस्थान डिस्कॉम द्वारा दायर की गई थी।

उसी तारीख के राज्य आयोग के आदेश द्वारा जिसमें सी. ई. आर. सी. द्वारा कुछ 'कानून में परिवर्तन' के दावों की अनुमति दी गई थी।

37. राज्य आयोग द्वारा अनुमति दिए गए 'कानून में परिवर्तन' के दावे निम्नानुसार हैं:

घरेलू कोयले पर देय रॉयल्टी की दर में परिवर्तन;

आई.

ii.

रेलवे (आई. आर.) और

'संचालन की सहमति' के लिए शुल्क में वृद्धि।

iii.

38. 'कानून में परिवर्तन' के दावे जिनकी राज्य आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, वे इस प्रकार हैं:

कोयले के मूल्य निर्धारण तंत्र में उपयोगी ऊष्मा मूल्य से परिवर्तन

1 .

(यूएचवी) सकल कैलोरी मूल्य आधार (जीसीवी) का आधार कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) द्वारा लिए गए कोयले के आकार शुल्क में वृद्धि

2 .

सतह परिवहन शुल्क में वृद्धि

3 .

कोयले के परिवहन पर व्यस्त मौसम अधिभार में वृद्धि

4 .

भारतीय रेलवे

कोयले के परिवहन पर लगाए गए विकास अधिभार में वृद्धि

5 .

रेलवे द्वारा

ईंधन समायोजन घटक का शुल्क

6 .

बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार का शुल्क

7 .

वन कर का शुल्क

8 .

रेल परिवहन के लिए कोयले के वर्गीकरण में बदलाव

9 .

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [वी. आर. गवई, जे.]

39. विवादित फैसले के माध्यम से, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने राजस्थान डिस्कॉम की अपील को खारिज कर दिया और आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी ए. पी. आर. एल. 'व्यस्त मौसम अधिभार', 'विकास अधिभार', 'बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार', 'वन कर' और 'वहन लागत' के आधार पर अपने दावों की अनुमति देता है। इससे व्यथित होकर राजस्थान डिस्कॉम ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

40. हमने राजस्थान डिस्कॉम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि और एपीआरएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी को सुना है।

41. श्री वी. गिरि प्रस्तुत करते हैं कि पी. पी. ए. में खंड 10 केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत करें के लिए संदर्भित है। वह प्रस्तुत करता है कि अतः विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने व्यस्त मौसम अधिभार, विकास से संबंधित मुद्दों पर 'कानून में परिवर्तन' लाभों की अनुमति देने में गलती की है।

अधिभार, बंदरगाह भीड़भाड़ शुल्क, वन कर और वहन लागत जो संविधान के अनुच्छेद 268 के लिए संदर्भित कर नहीं हैं। 42. डॉ. सिंघवी ने उसी तर्ज पर तर्क दिए जो अन्य अपीलों में दिए गए हैं।

सिविल अपील सं। 2935-2936 2020 का

43. ये अपीलें राजस्थान डिस्कॉम और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आम फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं।

और 29 जनवरी 2020 का आदेश, विद्वान एपीटीईएल द्वारा अपील सं। 284 2017 का और 2018 का अपील सं. 09। 44. राज्य आयोग द्वारा पारित 8 जून 2017 के आदेश को चुनौती देते हुए

ए. पी. आर. एल. द्वारा 2017 की अपील संख्या 284 दायर की गई थी।

'कानून में परिवर्तन' और वहन लागत के आधार पर कुछ घटकों पर अपने दावे की अस्वीकृति से व्यथित, जबकि 2018 की अपील संख्या 9 राजस्थान डिस्कॉम द्वारा दायर की गई थी, जो उन दावों से व्यथित थी जिन्हें राज्य आयोग द्वारा अनुमति दी गई थी।

45. 'कानून में परिवर्तन' के आधार पर जिन घटकों की अनुमति दी गई थी और जिनकी अनुमति नहीं दी गई थी, उनकी सूची इस प्रकार है:

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय

का

कानून के मदों में बदलाव

" श्री. नहीं।

आ

योग

रॉयल्टी पर शुल्क

(i) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास से प्रभावी

14.08.2015

ए.

अ

नुमति दी गई।

((ii) जिला खनिज फाउंडेशन से प्रभावी

12.01.2015

स्वच्छ भारत उपकर (एस. बी. सी.) का शुल्क

रेल परिवहन के लिए सेवा कर प्रभावी

अ

नुमति दी गई।

बी.

15.11.2015

स्वच्छ भारत उपकर की दर 0.5 प्रतिशत के साथ-साथ
से प्रभावी सेवा कर संचालन अवधि

एस.

अनु

मति नहीं है

15.11.2015

सेवा के साथ कृषि कल्याण उपकर (के. के. सी.) का शुल्क

रेल परिवहन के लिए कर और स्वच्छ भारत उपकर

अ

नुमति दी गई।

डी.

कृषि कल्याण उपकर का 0.50 प्रतिशत की दर से शुल्क
सेवा कर और स्वच्छ भारत उपकर संचालन

अनु

मति नहीं है

ई.

1 जून 2016 से अवधि।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 में संशोधन

अनु

मति नहीं है

एफ.

कोयला टर्मिनल अधिभार (सीटीएस) का शुल्क प्रभावी

अनु

मति नहीं है

जी.

22.08.2016 से

कोयले और लिग्नाइट से उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग

एच.

ताप विद्युत परियोजनाओं पर आधारित

अनु

मति नहीं है

सी. जी. पर्यावरण उपकार

आई.

अनु

मति नहीं है

सी. जी. विकास उपकार

जे.

अनु

मति नहीं है

पोत द्वारा माल के परिवहन पर सेवा कर

भारत के बाहर किसी स्थान से कस्टम स्टेशन तक

के.

अनु

मति नहीं है

भारत में निकासी

वहन लागत

एल.

अनु

मति नहीं है "

46. जैसा कि ऊपर कहा गया है, आदेश के उस हिस्से से व्यथित होना

जिसने अपने दावे को अस्वीकार कर दिया, ए. पी. आर. एल. ने विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष उपरोक्त अपील को प्राथमिकता दी, जबकि राजस्थान डिस्कॉम, आदेश के उस हिस्से से व्यथित होने के कारण, जिसने कुछ घटकों पर दावों की अनुमति दी थी, ने भी विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील दायर की।

47. विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने अपील को खारिज करते हुए

राजस्थान डिस्कॉम ने 'कानून में बदलाव' के आधार पर कुछ अन्य घटकों पर मुआवजे की अनुमति देकर आंशिक रूप से एपीआरएल की अपील की अनुमति दी।

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

48. जिन घटकों पर विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा 'कानून में परिवर्तन' लाभ प्रदान किए गए थे, वे इस प्रकार हैं:

(i) कोयला टर्मिनल अधिभार;

((ख)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकार;

(iii)

छत्तीसगढ़ विकास उपकार;

((iv)

स्वच्छ भारत उपकर में 0.50 प्रतिशत की दुर्लभ दर से परिवर्तन

संचालन अवधि के लिए सेवा कर;

(v)

सेवा पर 5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर में बदलाव
संचालन अवधि के लिए कर;

49. 'कानून में बदलाव' के आधार पर राहत देने के अलावा, विद्वान एपीटीईएल ने 'वहन लागत' भी प्रदान की।

50. 2018 की सिविल अपील संख्या 12055-12056 में दिए गए तर्कों के समान तर्क श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ द्वारा दिए गए थे।

राजस्थान डिस्कॉम की ओर से पेश होने वाले वकील के साथ-साथ उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा।

2019 की सिविल अपील संख्या 3123 और 2019 की सिविल अपील No.5372

2019 51. ये क्रॉस अपील हैं। बिहार स्टेट पावर (होल्लिंग) कंपनी लिमिटेड (इसके बाद) द्वारा 2019 की सिविल अपील दायर की गई है।

जी. एम. आर. कमलंगा एनर्जी लिमिटेड और जी. एम. आर. एनर्जी द्वारा "बिहार डिस्कॉम" के रूप में संदर्भित) और 2019 की सिविल अपील No.5372 दायर की गई है।

लिमिटेड (इसके बाद "जी. के. ई. एल". के रूप में संदर्भित), 2017 की अपील No.193 और 2018 की आई. ए. संख्या 449 में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित 21 दिसंबर 2018 के फैसले और आदेश को चुनौती देता है।

52. जी. के. ई. एल. द्वारा 2017 की अपील No.193 और 2018 की आई. ए. No.449 7 अप्रैल 2017 के सी. ई. आर. सी. के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जो "परिवर्तन" के आधार पर कुछ घटकों पर अपने दावों को अस्वीकार करने से व्यथित है।

कानून में '। बिहार डिस्कॉम ने विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश के उस हिस्से को चुनौती दी है जिसने 'कानून में बदलाव' के आधार पर जी. के. ई. एल. के दावों की अनुमति दी थी। 53. विवादित आदेश द्वारा, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने निम्नलिखित आधार पर दावे मंजूर किए:

एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन (कैप्टिव ब्लॉक को रद्द करना बनाम

((i)

टेपरिंग लिंकेज), [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ख)

व्यस्त मौसम अधिभार और विकासात्मक अधिभार,

((ग) वहन लागत; और

((iv) प्रीमियम मूल्य जोड़ें।

54. हमने विद्वान वकील श्री विश्व मुखर्जी को सुना है।

जी. के. ई. एल./जनरेटर और बिहार डिस्कॉम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री अनुश्री बर्धन की ओर से पेश हुए।

55. श्री विश्व मुखर्जी प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल.

साथ ही सी. ई. आर. सी. ने मुआवजे के दावे को इस आधार पर अस्वीकार करने में धोर गलती की है:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले के स्रोत में परिवर्तन।

((i)

(" 26 फरवरी 2014 को जारी अधिसूचना के माध्यम से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षिप्त में "ईसीएल") को एम. सी. एल.

सीआईएल;

((ख)

रेल से सड़क तक परिवहन के साधन में परिवर्तन

एम. सी. एल. द्वारा 29 सितंबर 2014 को जारी अधिसूचना;

न्यूनतम वैकल्पिक कर ("एमएटी") के शुल्क में वृद्धि

((iii)

संक्षेप में); और

कार्यशील पूँजी पर व्याज।

((iv)

जो राज्य का एक साधन है। इसी तरह, उन्होंने प्रस्तुत किया कि रेल से सड़क तक परिवहन के तरीके में परिवर्तन एमसीएल द्वारा जारी अधिसूचना के कारण हुआ था। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि, चूंकि, इन अधिसूचनाओं के कारण, कोयले के परिवहन की लागत में वृद्धि हुई, जिससे प्रतिस्थापन सिद्धांत, सीईआरसी

के साथ-साथ विद्वान भी लागू हुए। ए. पी. टी. ई. एल. को 'कानून में बदलाव' के आधार पर दावे मंजूर करने चाहिए थे। उन्होंने आगे कहा कि भारत संघ द्वारा एम. ए. टी. के शुल्क में वृद्धि भी की गई है और इस प्रकार, यह 'कानून में परिवर्तन' के बराबर भी होगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज भी राज्य के उपकरणों के आदेशों के कारण बढ़ाया गया था और इसलिए, इसके लिए मुआवजा भी दिया जाना चाहिए था।

57. बिहार डिस्कॉम्स के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने दावों की अनुमति देने में घोर गलती की है।

'कानून में परिवर्तन' के आधार पर कुछ घटक।

ए. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

2019 की सिविल अपील संख्या 6641

58. जी. के. ई. एल. द्वारा दायर यह अपील निर्णय से उत्पन्न होती है और

दिनांक 27 मई 2019, अपील में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित

95 2016 का, जिससे आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी गई।

59. जी. के. ई. एल. ने सी. ई. आर. सी. के समक्ष याचिका No.79/एम. पी./2013 दायर की जिसमें 'कानून में बदलाव' के आधार पर विभिन्न घटकों को लागू करने का दावा किया गया था।

सीएस।

60. सी. ई. आर. सी. ने 3 फरवरी 2016 के आदेश के माध्यम से अनुमति नहीं दी

निम्नलिखित घटकों के लिए संयोजन:

(क) कोयले के यू. एच. वी. से जी. सी. वी. आधारित मूल्य निर्धारण में परिवर्तन

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के लिए;
रेलवे माल ढुलाई शुल्क में वृद्धि/संशोधन

(ख)

रेल मंत्रालय और मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएँ
वित्त;

(ग)

न्यूनतम वैकल्पिक कर ("एमएटी") की दर में वृद्धि
दरें;

(घ)

ओडिशा राज्य में मूल्य वर्धित कर में वृद्धि;

(ई)

ओडिशा सरकार द्वारा;
कार्यशील पूंजी पर व्याज में वृद्धि

(च)

परिचालन अवधि के दौरान लागत में वृद्धि का लेखा।

61. इससे व्यथित होने के कारण, 2016 की अपील No.195 थी।

GKEL द्वारा लाल। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने आंशिक रूप से निष्कासन की अनुमति दी और कहा कि जी. के. ई. एल. निम्नलिखित पर मुआवजे का हकदार था:

डी. एस.

(i)

रेलवे माल ढुलाई शुल्क में वृद्धि/संशोधन विकास लागू करने के कारण रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएँ

अधिभार, व्यस्त मौसम अधिभार और सेवा कर;

((ख)

वैट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई

आगे बढ़ना;

(iii) गणना द्वारा मुआवजे का पता लगाने के बाद उपरोक्त वस्तुओं पर लागत/ब्याज ले जाना, जिसका मूल्यांकन संबंधित अधिसूचना/परिपत्र/[2023] 8 एस. सी. आर. की तारीख से किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित मंत्रालय/विभाग/से आदेश

भुगतान किए जाने तक सरकारी साधन।

62. अपीलार्थी-जी. के. ई. एल. ने इससे असंतुष्ट होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इस निर्देश के लिए प्रार्थना की है कि वह भी इसका हकदार है।

विभिन्न अन्य घटकों पर क्षतिपूर्ति, अर्थात् ,

(i) जल शुल्क में वृद्धि;

कोयले के मूल्य निर्धारण की यू. एच. वी. से जी. सी. वी. पद्धति में बदलाव;

((ख)

(

(ग) एम. ए. टी. की दर में वृद्धि; और

() (0 (iv) कार्यशील पूँजी पर ब्याज।

63. 2019 की सिविल अपील संख्या 3123 और 2019 की सिविल अपील No.5372 में दिए गए तर्कों के समान तर्क पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए थे।

सिविल अपील सं। 5583-5584 2021 का

64. बिहार डिस्कॉम द्वारा दायर ये अपीलें 6 अगस्त 2021 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसे विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने अपील में पारित किया था।

2019 की सं. 423 और 2021 की अपील No.173 में।

65. उक्त मामले में, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने 21 दिसंबर 2018 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित दावों को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में स्वीकार किया था। और जी. के. ई. एल. के कारण मुआवजे का निर्धारण करने के लिए मामले को सी. ई. आर. सी. को वापस भेज दिया:

लिकेज कोयले में कमी और एन. सी. डी. पी. में विचलन;

(अ)

कैप्टिव कोयला ब्लॉक को रद्द करना;

(ख)

(ग)

व्यस्त मौसम अधिभार और विकास का अधिरोपण

अधिभार;

((घ)

ऐड-ऑन प्रीमियम का शुल्क अधिसूचित मूल्य के ऊपर

कोयले का; और

(ङ) वहन लागत।

66. रिमांड पर, सी. ई. आर. सी. ने 16 सितंबर 2019 को आदेश पारित किया, जिससे वहन लागत सहित 'कानून में परिवर्तन' के आधार पर कुछ घटकों पर मुआवजा दिया गया। 67. यह तर्क देते हुए कि सी. ई. आर. सी. द्वारा पारित आदेश ने विद्वान जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा निर्देशित 'कानून में परिवर्तन' घटकों को प्रभावी नहीं बनाया।

बी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

ए. पी. टी. ई. एल., एक अपील 2019 की अपील संख्या 423 है जिसे जी. के. ई. एल. द्वारा विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. से पहले प्राथमिकता दी गई।

68. बिहार डिस्कॉम ने भी अपील No.173 के रूप में एक अपील दायर की थी।

सी. ई. आर. सी. द्वारा दिए गए लाभों से पीड़ित होने के कारण, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. से पहले, 2021 का।

69. विवादित आदेश के अनुसार, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने माना कि जी. के. ई. एल.

बिहार पी. पी. ए. के तहत दायित्वों से संबंधित अनुसूचित उत्पादन के अनुरूप घरेलू कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण वैकल्पिक कोयले की खरीद में शामिल व्यय की वसूली का हकदार था। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-जी. के. ई. एल. को पहले की तरह उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता थी जैसे कि कोई 'कानून में परिवर्तन' घटना नहीं हुई थी।

70. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री अनुश्री बर्धन-बिहार डिस्कॉम और श्री मनिंदर को सुना है।

सिंह, जी. के. ई. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हैं।

71. सुश्री अनुश्री बर्धन प्रस्तुत करती हैं कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. को 'कानून में परिवर्तन' का लाभ देना चाहिए था, जो इसे केवल 894.5 एम. डब्ल्यू. की कमी तक सीमित कर देता था, जो पी. पी. ए. में निर्दिष्ट राशि थी, न कि पूरे 1050 एम. डब्ल्यू. के लिए, जो कि स्थापित क्षमता है। वह आगे प्रस्तुत करती है कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने भी प्रीमियम पर अतिरिक्त राशि देने में गलती की थी।

टेपरिंग लिंकेज को तीन साल तक बढ़ाने का लेखा।

72. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि कोयले की आपूर्ति में कमी के संबंध में पहला मुद्दा है - संबंधित रूप से, यही बात एनर्जी वॉचडॉग बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर की गई है। केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग और अन्य 2, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और अन्य 3 (इसके बाद "अडानी राजस्थान मामला" के रूप में संदर्भित) और एमएसईडीसीएल बनाम। एपीएमएल और ओआरएस। (ऊपर)।

73. उन्होंने आगे कहा कि कैपिटल खदानों के संचालन में देरी किसी भी कारण से जी. के. ई. एल. के कारण नहीं थी।

वे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि मनोहर लाल शर्मा बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले के कारण कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया गया था। प्रधान सचिव और जी. के. ई. एल. भी उक्त अवधि के लिए लाभ के हकदार थे।

2 (2017) 14 एससीसी 80 3 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 697 4 (2014) 9
एससीसी 516 और 2014 (9) एससीसी 614 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74. जहाँ तक व्यस्त मौसम अधिभार का संबंध है, वह प्रस्तुत करता है कि तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है। वह प्रस्तुत करता है कि, किसी भी मामले में, उक्त शुल्क रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचना/परिपत्र जारी करके जारी किए जाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि रेलवे राज्य का एक साधन है, इसलिए सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. दोनों ने समवर्ती रूप से माना है कि जनरेटर 'कानून में परिवर्तन' के आधार पर मुआवजे का हकदार होगा।

2021 की सिविल अपील संख्या 39

75. डी. एन. एच.-डिस्कॉम द्वारा दायर यह अपील 13 अक्टूबर 2020 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसे विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा 2019 और आई. ए. सं. की अपील No.283 में पारित किया गया था। 2188 & 1229 सी. ई. आर. सी. द्वारा दिनांक 16 मई 2019 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न उक्त अपील को खारिज करते हुए।

76. डी. एन. एच.-डिस्कॉम ने केस-1 बोली प्रक्रिया के तहत दीर्घकालिक आधार पर बिजली की खरीद के लिए मार्च 2012 में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (संक्षेप में आर. एफ. पी.) जारी करके एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू की थी। आर. एफ. पी. के अनुसार, कट-ऑफ की तारीख 1 जून 2012 थी।

77. प्रतियोगी-जी. डब्ल्यू. ई. एल. एक स्तर पर 200 मेगावाट की कुल संविदित क्षमता की आपूर्ति के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा।

रुपये का शुल्क। 4.618 प्रति इकाई।

78. तदनुसार, डी. एन. एच. डिस्कॉम द्वारा 14 अगस्त 2012 को आशय पत्र (एल. ओ. एल.) जारी किया गया था। एक आवेदन/याचिका याचिका No.87/2012 के रूप में संयुक्त विद्युत नियामक के समक्ष दायर की गई

पी. पी. ए. के अनुमोदन और शुल्क को अपनाने के लिए आयोग (इसके बाद "संयुक्त आयोग" के रूप में संदर्भित)। उक्त याचिका में जी. डब्ल्यू. ई. एल. को भी सह-याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया गया था। संयुक्त आयोग ने 19 फरवरी 2013 के आदेश के माध्यम से पी. पी. ए. को मंजूरी दी। तदनुसार, पी. पी. ए. 21 मार्च 2013 को निष्पादित किया गया। 79. जी. डब्ल्यू. ई. एल. ने 'कानून में बदलाव' के आधार पर कुछ घटकों पर मुआवजे की मांग करते हुए सी. ई. आर. सी. के समक्ष याचिका संख्या 8/एम. पी./2014 दायर की।

सी. ई. आर. सी. द्वारा 1 फरवरी 2017 के आदेश के माध्यम से भी यही निर्णय लिया गया था। इससे व्यथित होकर, दोनों अपीलार्थी-डी. एन. एच.-डिस्कॉम और प्रतिवादी-जी. डब्ल्यू. ई. एल. ने विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील दायर की। अपील में, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने कुछ मुद्दों पर विचार करने के लिए 14 अगस्त 2018 के आदेश के माध्यम से मामले को सी. ई. आर. सी. को भेज दिया। 14 अगस्त 2018 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-डी. एन. एच.-डिस्कॉम ने जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड के समक्ष याचिका दायर की।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

इस न्यायालय के समक्ष अपील, 2018 की सिविल अपील No.11910 है। ने कहा कि

अपील के वर्तमान समूह में भी इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। 80. रिमांड पर, सी. ई. आर. सी. ने 16 मई 2019 को एक आदेश पारित किया और जी. डब्ल्यू. ई. एल./जनरेटर के दावे को 'भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन की योजना' (संक्षेप में 'शक्ति नीति') के प्रवर्तन के कारण 'कानून में बदलाव' के आधार पर अनुमति दी। इससे व्यथित होकर, डी. एन. एच.-डिस्कॉम ने विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील दायर की थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसे विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा खारिज कर दिया गया था।

निर्णय।

81. हमने डी. एन. एच.-डिस्कॉम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम और श्री निरंजन रेड्डी को सुना है,

प्रतिवादी-जी. डब्ल्यू. ई. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। 82. श्री सी. ए. सुंदरम प्रस्तुत करते हैं कि जी. डब्ल्यू. ई. एल. द्वारा दी गई प्रस्तुति से यह स्पष्ट था कि यह इस आधार पर दिया गया था कि कोयले की आपूर्ति केवल 65 प्रतिशत तक सीमित होगी। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस आधार पर 'कानून में परिवर्तन' के कारण लाभ का अनुदान कि सी. आई. एल. द्वारा 100% आश्वासन दिया गया था, स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय और आदेश को उस हद तक अलग रखा जाना चाहिए।

83. इसके विपरीत, श्री निरंजन रेड्डी प्रस्तुत करते हैं कि जी. डब्ल्यू. ई. एल. की बोली 8 जून 2012 को प्रस्तुत की गई थी, जिस तारीख को एन. सी. डी. पी. 2007 प्रस्तुत की गई थी।

बलपूर्वक। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, बाद में, एन. सी. डी. पी. 2007 को 31 जुलाई 2013 को संशोधित किया गया था और उसके बाद 22 मई 2017 को शक्ति नीति लागू हो गई है और इस तरह, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय और आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं है।

2022 की सिविल अपील संख्या 5005 और 2022 की सिविल अपील संख्या 4089

2021 और 2022 का 40, क्रमशः रतन इंडिया पावर लिमिटेड (इसके बाद "रतन इंडिया" के रूप में संदर्भित) और अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (संक्षेप में, "एपीएमएल") द्वारा दायर किया गया, जिससे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पारित 1 जनवरी 2019 और 3 अगस्त 2018 के आदेशों को चुनौती दी गई। 2018 के मामले संख्या 227 और 2018 के मामले संख्या 124 में विनियामक आयोग (इसके बाद 'एम. ई. आर. सी.' के रूप में संदर्भित)।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

85. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत: रतन इंडिया ने 22 अप्रैल 2010 और 5 जून 2010 को एमएसईडीसीएल के साथ 1200 मेगावाट की कुल बिजली की आपूर्ति के लिए पीपीएएस में प्रवेश किया है।

रुपये का स्तरीकृत शुल्क। 25 वर्षों की अवधि के लिए 3.260 KWH। इसने एम. ई. आर. सी. के समक्ष एक याचिका दायर की, जो 2018 का मामला संख्या 227 है, जिसमें सी. आई. एल. द्वारा 19 दिसंबर 2017 को जारी परिपत्र के कारण 'कानून में बदलाव' के आधार पर मुआवजे का दावा किया गया है, जिसके अनुसार उसने निकासी सुविधा शुल्क (संक्षेप में, "ई. एफ. सी.") लगाया है। इसे एम. ई. आर. सी. द्वारा 1 जनवरी 2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इसी तरह की याचिका 2018 का मामला संख्या 124 भी ए. पी. एम. एल. द्वारा दायर की गई थी, जिसमें एम. ई. आर. सी. के समक्ष इसी तरह का दावा किया गया था, जिसे एम. ई. आर. सी. ने भी 3 अगस्त 2018 के अपने पहले के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया था।

86. इससे व्यथित होकर, रतन इंडिया ने 2021 की अपील संख्या 118 दायर की थी और एपीएमएल ने 2022 की अपील संख्या 40 को प्राथमिकता दी थी। विवादित आदेश द्वारा, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने 19 दिसंबर 2017 के परिपत्र के माध्यम से सी. आई. एल. द्वारा लगाए गए ई. एफ. सी. को 'कानून में परिवर्तन' माना था।

घटना और, तदनुसार, उत्पादकों को उक्त आधार पर मुआवजे का हकदार ठहराया। इससे व्यथित होकर, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

87. हमने अपर सॉलिसिटर जनरल (संक्षेप में, "ए. एस. जी.") श्री बलबीर सिंह और विद्वान वकील श्री जी. साईकुमार को सुना है।

अपीलार्थी और श्री साजन पूवय्या की ओर से उपस्थित होते हुए, 2022 की सिविल अपील संख्या 5005 में उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और 2022 की सिविल अपील संख्या 4089 में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विश्वो मुखर्जी।

88. श्री बलबीर सिंह ने साउथईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और एपीएमएल के बीच 28 दिसंबर 2012 को हुए कोयला आपूर्ति समझौते (संक्षेप में, "सीएसए") के खंड 9 पर भरोसा करते हुए कहा कि

सी. एस. ए. परिभाषित करता है कि कोयले का आधार मूल्य क्या होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त सी. एस. ए. का खंड 9.2 विशेष रूप से अन्य शुल्कों के लिए प्रावधान करता है जो अनुमेय हैं। सीएसए के खंड 9.4 पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी मामलों में, आपूर्ति किए गए कोयले के परिवहन के तरीके के बावजूद, पूरा माल ढुलाई शुल्क खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि ई. एफ. सी. एक वैधानिक शुल्क के चरित्र में भाग नहीं लेता है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि, किसी भी मामले में, इसमें कानून का बल नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ए. पी. टी. ई. एल. के पास जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड है।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

'कानून में परिवर्तन' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 19 दिसंबर 2017 को सी. आई. एल. का परिपत्र आयोजित करने में गलती की।

89. श्री सिंह ने आगे कहा कि विलंबित भुगतान अधिभार (संक्षेप में, "एल. पी. एस".) के लिए प्रदान की गई दर पर वहन लागत का भुगतान करने का निर्देश भी कानून में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने अडानी राजस्थान मामले (उपरोक्त) में वहन लागत का भुगतान 9 प्रतिशत की दर से करने का निर्देश दिया है और इसलिए वर्तमान मामले में इसे उसी दर से भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए था।

90. श्री सिंह अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा करते हैं। संघ का

भारत और अन्य इस प्रस्ताव के समर्थन में कि सी. आई. एल. कोयले की कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र है और भारत संघ का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

91. इसके विपरीत, श्री पूवय्या ने कहा कि शुल्क प्रकृति में अनिवार्य है। जब तक उक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक कोयले की आपूर्ति नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि सी. आई. एल. सरकार का एक साधन है, इसलिए इसके द्वारा जारी आदेश पी. पी. ए. में परिभाषित "कानून" की परिभाषा के भीतर एक कानून के बराबर होगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक वहन लागत का संबंध है, अनुच्छेद 11.8 में पी. पी. ए. में एक विशिष्ट प्रावधान है। 3, जो पक्षों के लिए बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स द्वारा उत्पादन करने वाली कंपनियों के बकाया का भुगतान न करने के कारण, उत्पादन करने वाली कंपनियों को ऋण लेना आवश्यक है।

बाजार दर पर निधियाँ और इस तरह, प्रतिस्थापन सिद्धांत को लागू करते हुए, यह समझौते के तहत प्रदान की गई लागत को वहन करने का हकदार है।

III. अतिरिक्त मुद्दे

92. पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, हम पाते हैं कि, उन तीन मुद्दों के अलावा जो पहले से ही इसके द्वारा तय किए गए थे।

एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामले में न्यायालय एपीएमएल और ओआरएस। (ऊपर), ये मुद्दे कि क्या निम्नलिखित घटकों को 'कानून में परिवर्तन' घटनाओं के रूप में माना जा सकता है, यहां विचार के लिए आते हैं:

(i)

बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार;

कोयले की गुणवत्ता पर एम. ओ. ई. एफ. अधिसूचना;

(ख)

एन. सी. डी. पी. में बदलाव के कारण लिंकेज कोयले में कमी;

(iii)

(iv) वन कर;

5 (2007) 2 एससीसी 640 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रीमियम कीमत जोड़ें।

(v)

(€ vi) निकासी सुविधा शुल्क (ई. एफ. सी.)।

इसके अलावा, एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न कर/शुल्क

सरकारें भी 'कानून में बदलाव' की घटनाओं के दायरे में आती हैं या नहीं। दूसरा सवाल जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या जनरेटर किस दर पर 'वहन लागत' के हकदार होंगे।

IV. समन्वय

93. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, हमें "कानून" शब्द का अर्थ लगाना होगा, जिसे पी. पी. ए. में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

“ ” "कानून" का अर्थ है, इस समझौते के संबंध में, भारत में लागू बिजली कानूनों और किसी भी कानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम, या किसी भी समझौते की कोई व्याख्या सहित सभी कानून। उनमें से एक भारतीय सरकारी साधन द्वारा और कानून के बल के साथ और आगे सभी लागू नियमों, विनियमों, आदेशों, भारत सरकार द्वारा अधिसूचनाओं को शामिल करेगा।

उनमें से किसी के अनुसार या उसके तहत उपकरण और इसमें सीईआरसी के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश शामिल होंगे और

एम. ई. आर. सी. "

94. "कानून" शब्द की परिभाषा के अवलोकन से ही स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि "कानून" शब्द का अर्थ बिजली सहित सभी कानून होंगे।

भारत में लागू कानून और कोई भी कानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम, या किसी भारतीय द्वारा उनमें से किसी की कोई व्याख्या

सरकारी साधन और कानून का बल होना। इससे यह भी पता चलेगा कि "कानून" शब्द में भारतीय सरकार द्वारा लागू सभी नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं भी शामिल होंगी।

साधन और इसमें सीईआरसी और एमईआरसी के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश भी शामिल होंगे।

95. किसी भी मामले में, यह मुद्दा कि "कानून" के बराबर क्या होगा, अब एकीकृत नहीं है। एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 57. दिनांकित 31-7-2013 पत्र और संशोधित शुल्क नीति दोनों अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए जा रहे वैधानिक दस्तावेज हैं और कानून के बल पर हैं। यह स्पष्ट है कि जहां तक भारतीय कोयले की खरीद का संबंध है, उस हद तक जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

कोल इंडिया और अन्य भारतीय स्रोतों से आपूर्ति में कटौती की जाती है, इन दस्तावेजों के साथ पढ़ा गया पी. पी. ए. खंड 13.2 में प्रदान करता है कि कानून में परिवर्तन के परिणामों का निर्धारण करते समय, पक्षों को इस सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा कि क्षतिपूर्ति करने का उद्देश्य

कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से प्रभावित पक्ष को आर्थिक स्थिति में बहाल करना है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा, पी. पी. ए. के संचालन की अवधि के लिए, इसमें किसी भी वृद्धि/कमी के लिए मुआवजा

करेंगे "।

96.

ऊर्जा के मामले में इस न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण लिया गया

अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) में इस अदालत के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने वॉचडॉग (ऊपर) को मंजूरी दी है और इसके बाद इस अदालत ने भी जब अपीलों के इस समूह में से दो जुड़े मामले थे एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। एपीएमएल और ओआरएस। (ऊपर)। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीआईएल भारत सरकार का एक साधन है और जहां तक ईंधन की कीमत का संबंध है, इसके आदेश बाध्यकारी हैं

इसकी सभी सहायक कंपनियों पर।
होगा, जो इस प्रकार है:

97. सी. एस. ए. के खंड 9 का उल्लेख करना आगे प्रासंगिक

" 9.0 कोयले की कीमत:

कोयले की आपूर्ति के लिए "कोयले का वितरित मूल्य"
इस समझौते के लिए आधार मूल्य, अन्य शुल्कों और सांविधिक शुल्कों का योग होगा, जैसा कि वितरण के समय लागू होता है

कोयला "।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कोयले की कीमत में आधार मूल्य, अन्य शुल्क और वितरण के समय लागू वैधानिक शुल्क शामिल हैं। कोयले से।

सरकारी साधन। 99. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि ऐसे सभी अतिरिक्त शुल्क जो आदेशों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, विनियमों, [2023] 8 एस. सी. आर. के कारण देय हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कट-ऑफ तिथि के बाद राज्य की संस्थाओं द्वारा जारी किए गए उपकरणों आदि को 'कानून में परिवर्तन' की घटनाएँ माना जाएगा। उत्पादक कट-ऑफ तिथि के बाद होने वाले ऐसे परिवर्तनों पर प्रतिस्थापन सिद्धांत पर मुआवजे के हकदार होंगे।

100. इस प्रकार रखने के बाद, अब हम कुछ घटकों पर विचार करेंगे जो इनमें से अधिकांश अपीलों में सामान्य हैं।

व्यस्त मौसम अधिभार, विकास अधिभार और बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार

101. जहाँ तक व्यस्त मौसम अधिभार में वृद्धि की बात है, विकास

कोयले के परिवहन पर अधिभार और भारतीय रेलवे द्वारा बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार का संबंध है, ज्ञात एपीटीईएल ने पाया था कि भारतीय रेलवे राज्य का एक साधन है। यह पाया गया है कि व्यस्त मौसम अधिभार, विकास अधिभार और बंदरगाह

रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे के माध्यम से जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के माध्यम से समय-समय पर भीड़भाड़ अधिभार में वृद्धि की गई।

बोर्ड। 102. रेलवे बोर्ड, भारत सरकार के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ V. मेसर्स ऑब्जर्वर पब्लिकेशंस (पी) लिमिटेड ने रेलवे बोर्ड को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य माना है।

103. इस प्रकार, ज्ञात ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकी कि व्यस्त मौसम अधिभार पर भुगतान किए जाने वाले शुल्कों का संशोधन,

'रेलवे बोर्ड' द्वारा समय-समय पर विकास अधिभार और बंदरगाह भीड़भाड़ शुल्क 'कानून में बदलाव' के दायरे में आएंगे।

कोयले की गुणवत्ता पर एमओईएफ अधिसूचना

104. जहाँ तक कोयले की गुणवत्ता पर एम. ओ. ई. एफ. की अधिसूचना का संबंध है, एम. ओ. ई. एफ. ने 2 जनवरी 2014 की अधिसूचना के माध्यम से, विशेष कटौती की तारीख, यानी 1 जून 2012 के बाद, 34 प्रतिशत से कम राख सामग्री वाले लाभान्वित कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली परियोजनाओं को अनिवार्य कर दिया है। मसौदा

11 जुलाई 2012 की एम. ओ. ई. एफ. की अधिसूचना 2 जनवरी 2014 की अंतिम अधिसूचना में समाप्त हुई। कल्पना के बिना, क्या यह हो सकता है

यह कहा जा सकता है कि एम. ओ. ई. एफ. राज्य का साधन नहीं है।

105. उक्त अधिसूचना के अनुसार, एमओईएफ ने बिजली परियोजनाओं को अनिवार्य कर दिया है

34 प्रतिशत से कम राख वाले लाभकारी कोयले का उपयोग करना। मान लीजिए,

6 (1972) 2 एससीसी 266 जीएमआर वारोरा एनर्जी लिमिटेड। वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

कट-ऑफ तिथि से पहले, इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 11 जुलाई 2012 और 2 जनवरी 2014 की उक्त अधिसूचनाएँ यह "कानून में परिवर्तन" के बराबर होगा। इस प्रकार, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है कि यह 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा।

एन. सी. डी. पी. में बदलाव के कारण लिकेज कोयले में कमी

106. जहां तक कोयला मंत्रालय (संक्षेप में "एम. ओ. सी".) द्वारा जारी एन. सी. डी. पी. में परिवर्तनों के कारण लिकेज कोयले में कमी का संबंध है, मुद्दा अब एकीकरण के लिए नहीं है। यह न्यायालय एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) के मामले में और इसी तरह अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) और हाल ही में एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम. एपीएमएल और ओआरएस। (सुप्रा) ने माना है कि एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा।

वन कर

107. जहां तक वन कर का संबंध है, अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि वन क्षेत्र में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("एस. ई. सी. एल".) खदानों से खनन और परिवहन पर कोई वन कर लागू नहीं था। छत्तीसगढ़ पारगमन (वन उपज नियम) 2001 के प्रावधानों के तहत पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, वन विभाग की अधिसूचना के माध्यम से 7 रुपये प्रति टन की दर से शुल्क लगाया गया था। निर्विवाद रूप से, उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग द्वारा जारी की जाती है, जो राज्य का एक साधन है। इस प्रकार, उस संबंध में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

प्रीमियम कीमत जोड़ें

108. जहाँ तक 'प्रीमियम मूल्य में वृद्धि' का संबंध है, निर्विवाद रूप से,

' कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को रद्द करने और गो-नो-गो नीति के कारण अत्यधिक देरी के कारण 'ऐड ऑन प्रीमियम' का भुगतान करना आवश्यक था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा अपनाया गया तर्क विकृत और मनमाना है।

निकासी सुविधा शुल्क (ईएफसी)

109. निर्विवाद रूप से, सी. आई. एल. द्वारा 19 दिसंबर 2017 के अपने परिपत्र के माध्यम से ई. एफ. सी. लागू किया गया था।

110. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सी. आई. एल. राज्य का एक साधन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कट-ऑफ तिथि पर कोई [2023] 8 एस. सी. आर. नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. एफ. सी. की आवश्यकता, जिसे केवल 19 दिसंबर 2017 को लागू किया गया है। इस प्रकार, सी. आई. एल. का 19 दिसंबर 2017 का परिपत्र भी 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा। 111. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह भी विवाद में नहीं है कि ई. एफ. सी. को उत्पादकों द्वारा आधार मूल्य, अन्य शुल्कों और कोयले की डिलीवरी के समय वैधानिक शुल्कों का भुगतान करते हुए भुगतान किया गया है। इस प्रकार, नहीं

उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

112. यह हमें वहन लागत के संबंध में समस्या के साथ छोड़ देता है।

वहन लागत

113. यही वह मुद्दा है जिस पर डिस्कॉम्स और जनरेटरों के बीच गंभीर प्रतिस्पर्धा है।

114. एक ओर, यह डिस्कॉम का निवेदन है कि चूंकि पी. पी. ए. एस. में इसका कोई विवरण नहीं है, इसलिए वहन लागत देने की दर एक उचित दर होनी चाहिए। इसके विपरीत यह है कि जनरेटरों का प्रस्तुत करना कि इसमें एक विशिष्ट प्रावधान है

पी. पी. ए. में यह प्रावधान है कि विलंब भुगतान अधिभार के लिए निर्दिष्ट दर के अनुसार वहन लागत का भुगतान किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

यह पी. पी. ए. में प्रदान किया गया है ताकि प्रतिस्थापन सिद्धांत को प्रभावी बनाया जा सके।

115. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लेख करना उचित होगा, जो अधिकांश पी. पी. ए. एस. में लगभग आम हैं।

" 11. बिलिंग और भुगतान। —

11.3 . मासिक बिलों का भुगतान। —

11.3. 4 . किसी भी खरीदार द्वारा निर्धारित तिथि से अधिक मासिक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में, खरीदार द्वारा विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय बकाया भुगतान की राशि पर, लागू एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष से दो (2) प्रतिशत की दर से विक्रेता को विलंब भुगतान अधिभार देय होगा, जिसकी गणना दैनिक आधार पर (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) की जाती है।

*** जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.)
[बी. आर. गवई, जे.]

11.8 . पूरक बिल का भुगतान। —

11.8. 1 . कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर विधेयक ला सकता है।

(" अनुपूरक बिल ") निम्नलिखित के कारण भुगतान के लिए

((ii) अनुसूची 5 के प्रावधानों के अनुसार मापदंडों में परिवर्तन के लिए शुल्क भुगतान; या
((ग) अनुच्छेद 13 में उपबंधित विधि में परिवर्तन और ऐसा विधेयक -

दूसरे पक्ष द्वारा भुगतान किया गया।

11.8. 3 . पूरक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में

बिलिंग की तारीख से एक महीने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा, अनुच्छेद 11.3 में मासिक बिल पर लागू होने वाली समान शर्तों पर विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाएगा। 4 . "

116. अनुच्छेद 11 का अवलोकन। 4 पी. पी. ए. से पता चलेगा कि किसी भी खरीदार द्वारा मासिक बिल के भुगतान में उसकी नियत तारीख से अधिक देरी होने की स्थिति में, खरीदार द्वारा विक्रेता को देय देरी के प्रत्येक दिन के लिए देय बकाया भुगतान की राशि पर, लागू स्टेट बैंक अग्रिम दर ("एस. बी. ए. आर".) प्रति वर्ष से 2 प्रतिशत अधिक की दर से विलंब भुगतान अधिभार देय होगा। पी. पी. ए. का अनुच्छेद 11.8 पूरक बिल के भुगतान से संबंधित है। यह किसी भी पक्ष को कुछ घटनाओं के कारण भुगतान के लिए दूसरे पक्ष पर पूरक बिल उठाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 11.8 का खंड (iii)। 1 पी. पी. ए. का अनुच्छेद 13 में दिए गए 'कानून में परिवर्तन' से संबंधित है। इसके लिए दूसरे पक्ष को बिल का भुगतान करना पड़ता है। अनुच्छेद 11.8। 3 पी. पी. ए. का यह भी प्रावधान है कि किसी भी पक्ष द्वारा बिलिंग की तारीख से एक महीने से अधिक समय तक पूरक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में, विलंब भुगतान अधिभार अनुच्छेद 11.3 में मासिक बिल पर लागू होने वाली समान शर्तों पर देय होगा। 4 .

अनुच्छेद 11, जो 'बिलिंग' से संबंधित है और अनुच्छेद 13, जो 'कानून में परिवर्तन' से संबंधित है, के प्रावधानों पर विचार करने के बाद अन्य ने इस प्रकार कहा है: 7 (2019) 5 एससीसी 325
[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9. यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद 13.4। 1 यह स्पष्ट करता है कि कानून में परिवर्तन के कारण मासिक शुल्क भुगतान में समायोजन कानून में परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगा [खंड 4 का उपखंड (i) देखें], यदि कानून में परिवर्तन कानून को अपनाने, उद्घोषणा, संशोधन, पुनः अधिनियमित करने या निरस्त करने या कानून में परिवर्तन के माध्यम से होता है। इसके विपरीत, यदि कानून में परिवर्तन किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय या सरकारी साधन द्वारा कानून की व्याख्या में परिवर्तन के कारण होता है, तो मामला खंड 4 के उपखंड (ii) के तहत आएगा, जिस मामले में, मासिक शुल्क भुगतान उक्त आदेश की तारीख से प्रभावी होगा।

सक्षम प्राधिकारी/न्यायाधिकरण या सरकारी साधन का निर्णय। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 13.4। 1 पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13.2 के अधीन है।

10. अनुच्छेद 13.2 एक अंतर्निहित प्रतिस्थापन सिद्धांत है जो कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति देता है और जो

मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से, प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह होगा कि इस खंड द्वारा एक कल्पना बनाई गई है, और पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी पक्ष को नागरिक कानून में समझे गए पुनर्स्थापन का लाभ दिया जाना चाहिए। हालाँकि, अनुच्छेद 13.2 इस तरह की बहाली को दो अलग-अलग अवधियों में विभाजित करता है। पहली अवधि "निर्माण अवधि" है जिसमें शुल्क में परियोजना की पूंजी लागत की वृद्धि/कमी को एक निश्चित सूत्र द्वारा नियंत्रित किया जाना है। हालाँकि, विक्रेता को खरीददार को इस तरह की वृद्धि का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करना होगा।

कानून में इस तरह के परिवर्तन के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में कमी और उसी के रूप में विवाद के मामले में, पी. पी. ए. के अनुच्छेद 17 के अनुसार एक विवाद समाधान तंत्र का सहारा लिया जाना है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्षतिपूर्ति केवल किसी भी पक्ष को उस तारीख से देय है जिस दिन कुल वृद्धि/कमी उसमें बताई गई राशि से अधिक होती है।

11. जहाँ तक "संचालन अवधि" का संबंध है, क्षतिपूर्ति

विक्रेता को राजस्व या लागत में किसी भी वृद्धि/कमी के लिए निर्धारित किया जाना है और ऐसी तारीख से प्रभावी होना है जो उपयुक्त आयोग द्वारा तय की जाती है। यहां फिर से, यह मुआवजा केवल विक्रेता को राजस्व या लागत में वृद्धि/कमी के लिए देय है यदि यह लेटर ऑफ़ क्रेडिट जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड के 1 प्रतिशत के बराबर राशि से अधिक है।

बी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

एक अनुबंध वर्ष के लिए कुल मिलाकर। इसलिए, अनुच्छेद 13.2 के पठन से जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि उपखंड (ए) और (बी) दोनों में एक निश्चित सीमा को पार करने की स्थिति में प्रतिस्थापन सिद्धांत लागू होते हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामला उपखंड (बी) द्वारा कवर किया गया है और उपरोक्त सीमा को पार कर दिया गया है। कानून में बदलाव का दावा करने के लिए तंत्र तब निर्धारित किया जाता है पी. ए. का अनुच्छेद 13.3।

118. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक "संचालन अवधि" का संबंध है, किसी भी वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति /

विक्रेता के लिए राजस्व या लागत में कमी का निर्धारण और प्रभाव ऐसी तारीख से किया जाना है जो उपयुक्त आयोग द्वारा तय की जाती है। इसमें है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्षतिपूर्ति केवल विक्रेता को राजस्व या लागत में वृद्धि/कमी के लिए देय है यदि यह एक अनुबंध वर्ष के लिए कुल मिलाकर ऋण पत्र के 1 प्रतिशत के बराबर राशि से अधिक है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिस्थापन सिद्धांत एक निश्चित मामले में लागू होते हैं

सीमा पार हो गई है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अंतर्निहित प्रतिस्थापन सिद्धांत इस तरह के 'कानून में परिवर्तन' से प्रभावित पक्ष को मुआवजा देता है और प्रभावित पक्ष को मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से बहाल किया जाना चाहिए।

समान आर्थिक स्थिति जैसे कि 'कानून में परिवर्तन' नहीं हुआ था।

119. पैराग्राफ 9 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होगा कि यदि 'कानून में परिवर्तन' गोद लेने के माध्यम से होता है, तो

कानून की घोषणा, संशोधन, पुनः अधिनियमन या निरसन या 'कानून में परिवर्तन', यह उस तारीख से प्रभावी होना चाहिए जिस दिन ऐसा परिवर्तन किया गया था।

होता है। 120. इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य विद्युत के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा।

वितरण कंपनी लिमिटेड v. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और अन्य:

" 173. एपीटीईएल ने सही पाया कि: (महाराष्ट्र प्रदेश

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल.

13] , एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल पैरा 13)

" 13. इसके विपरीत, एल. पी. एस. की गणना करते समय लागू की जाने वाली दर में किसी भी स्वतः संज्ञान परिवर्तन के बारे में एक सचेत बहिष्कार है, इस पर बहस करना गलत है

8 (2022) 4 एससीसी 657 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह धारणा कि अनुबंध स्वचालित परिवर्तन की अनुमति देता है

सिस्टम "।

(जोर दिया गया)

174. यह न्यायालय श्री सिंह की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि एल. पी. एस. शुल्क नहीं है, गलत है। अभिव्यक्ति शुल्क के अर्थ पर विचार किया जाना चाहिए, और बिजली खरीद समझौतों के प्रासंगिक प्रावधान के संदर्भ में एपीटीईएल द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है। शुल्क का शब्दकोश अर्थ शुल्क हो सकता है। हालांकि, चरण 1 के अनुच्छेद 13 और चरण 2 बिजली खरीद समझौतों के अनुच्छेद 10 में, शुल्क का अर्थ है मासिक शुल्क और कानून में बदलाव के परिणामस्वरूप शुल्क समायोजन, बिजली की आपूर्ति के संबंध में मासिक शुल्क का है।

175. श्री रोहतगी, श्री सिंघवी, श्री मुखर्जी और श्री मुखर्जी के माध्यम से पेश प्रतिवादी बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा तर्क दिया गया। क्रमशः सुश्री आनंद, एल. पी. एस. केवल तभी देय होता है जब मासिक बिलों के भुगतान में देरी होती है और अन्यथा नहीं।

176. एल. पी. एस. का उद्देश्य समय पर लागू करना और/या प्रोत्साहित करना है।

प्रापक अर्थात् अपीलार्थी द्वारा शुल्क का भुगतान। दूसरे शब्दों में, एल. पी. एस. खरीदार को भुगतान में देरी करने से रोकता है।

शुल्क लेते हैं। एल. पी. एस. की दर का शुल्क पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है।

एल. पी. एस. की दरों के आधार पर परिवर्तन उस दर को प्रभावित नहीं करता है जिस पर बिजली खरीद समझौतों के तहत बिजली बेचने और खरीदने पर सहमति हुई थी। पुनर्स्थापन का सिद्धांत

बिजली खरीद समझौतों के कानूनी प्रावधानों में बदलाव

शुल्क के संबंध में आकर्षित होते हैं।

177. एल. पी. एस. को बिजली की आपूर्ति के लिए वहन लागत या वास्तविक लागत के बराबर नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी का संविदात्मक दायित्व है कि वह बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए चालानों का समय पर भुगतान करे, जो निश्चित रूप से जांच के अधीन है और उसी का सत्यापन। श्री मुकुल रोहतगी का कहना है कि यदि वित्तपोषण लागत एल. पी. एस. की दर से बहुत कम होती, जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है, तो अपीलार्थी कम व्याज दर पर धन जुटा सकता था, बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा जुटाए गए चालान का समय पर भुगतान कर सकता था और एल. पी. एस. से बच सकता था।

178. यह प्रस्ताव कि अदालतें पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से निष्पादित अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती हैं, अच्छी तरह से तय है। न्यायालय अपनी व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड को फिर से नहीं लिख सकता है या एक नया अनुबंध नहीं बना सकता है।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

पीपुल्स कॉप। बैंक लिमिटेड, (2020) 13 एस. सी. सी. 564, पैरा 20], सुश्री दिव्या आनंद द्वारा उद्धृत। यह अपील पी. पी. ए. की शर्तों पर फिर से बातचीत करने का एक प्रयास है, जैसा कि सुश्री दिव्या आनंद और अन्य वकीलों ने भी तर्क दिया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतें पक्षों द्वारा वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं, यदि शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं। एक अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षों के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नाभा पावर में माना गया है। लिमिटेड वी. पंजाब एस. पी. सी. एल. [नाभा पावर लिमिटेड बनाम। पंजाब एसपीसीएल,

(2018) 11 एस. सी. सी. 508, पैरा 45 और 72: (2018) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1], सुश्री आनंद द्वारा उद्धृत।

121. इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि डिस्कॉम्स के पास है

बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा उठाए गए चालानों का समय पर भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व, जांच और सत्यापन के अधीन

एक ही। इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि वित्त पोषण लागत एल. पी. एस. की दर से बहुत कम थी। इस न्यायालय ने इस प्रस्ताव को दोहराया है कि अदालतें पक्षों के बीच निष्पादित किए गए अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती हैं। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं तो वह पक्षों द्वारा वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह माना गया है कि अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षों के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं।

122. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, पी. पी. ए. का अनुच्छेद 11.8 किसी भी पक्ष को अनुच्छेद 13 में प्रदान किए गए 'कानून में परिवर्तन' के कारण दूसरे पक्ष पर पूरक विधेयक उठाने का अधिकार देता है और ऐसे बिलों का भुगतान किसी भी पक्ष द्वारा किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 11.8। 3 पीपीए का

विशेष रूप से प्रदान करता है कि भुगतान में देरी की स्थिति में बिलिंग की तारीख से एक महीने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा पूरक बिल, अनुच्छेद 11.3 में मासिक बिल पर लागू होने वाली समान शर्तों पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा। 4 . अनुच्छेद 11.3। 4 पीपीए का

विशेष रूप से खरीदार द्वारा विक्रेता को लागू एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक की दर से विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाता है। विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर गणना की गई बकाया भुगतान की राशि (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) पर वर्ष।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

123. हाल ही में, यह अदालत, उत्तर हरियाणा बिजली के मामले में

एन निगम लिमिटेड और एक अन्य वी। अदानी पावर (मुंद्रा) टेड और अनदर 'के पास इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने का अवसर था। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 20. यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 13.2 में समाहित प्रतिस्थापन सिद्धांत परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए प्रभावी होंगे।

कानून में। हम विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं

[अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम सीईआरसी, 2021 एससीसी ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 67], जिसमें यह अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

कि प्रतिवादी 1 अदानी पावर ने बदलाव का दावा करना शुरू कर दिया था

इस दावे को निपटाने के लिए कई मंचों से संपर्क किया गया। उत्तरदाता 1 अदानी पावर अंततः क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सफल रहा। एफ. जी. डी. इकाई केवल 28-3-2018 पर है, लेकिन वहन लागत के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था। वहन लागत से संबंधित राहत प्रत्यर्थी 1 अदानी पावर को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 13-4 के आदेश के माध्यम से दी गई थी।

2018 [अदानी पावर लिमिटेड बनाम सी. ई. आर. सी., 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल 5]

(2019) 5 एससीसी 325: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 657] एक बार प्रत्यर्थी 1 अदानी पावर के पक्ष में वहन लागत स्वीकृत हो जाने के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि वहन लागत पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय सरल ब्याज के आधार पर की जानी चाहिए। वहन लागत पर चक्रवृद्धि ब्याज का अनुदान और वह भी कानूनी घटना में परिवर्तन की घटना की तारीख से ध्वनि तर्क पर आधारित। वहन लागत पर ब्याज देने के पीछे का विचार दूर की बात नहीं है, इसका उद्देश्य एक ऐसे पक्ष को पुनर्स्थापित करना है जो कानूनी घटना में बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है और इसे अपने मूल रूप में बहाल करना है।

आर्थिक स्थिति जैसे कि कानूनी घटना में इस तरह का बदलाव नहीं हुआ था

जगह।

XXX XXX XXX

23. हम अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुति से आश्चर्य नहीं हैं कि चूंकि उनके लिए कोई दोष नहीं है

राशि के निर्धारण में देरी, वे नहीं हो सकते हैं

वहन लागत पर ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से ग्रस्त; और न ही इस तर्क में कोई सार है कि

3) 2 एससीसी 624 जीएमआर वारोरा एनर्जी लिमिटेड। वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

पी. पी. ए. में उस तारीख से चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है जब कानूनी घटना में बदलाव हुआ था।

24. पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 में निहित पुनर्स्थापनात्मक सिद्धांतों की पूरी अवधारणा को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। उक्त सिद्धांत जो किसी पक्ष को धन के समय मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति करने को नियंत्रित करता है, वही सिद्धांत है जिसे लागू किया जाएगा।

और कानूनी घटना में परिवर्तन के कारण वहन लागत पर ब्याज अनुदान के लिए आवेदन किया। इसलिए, अनुच्छेद 11.3 पर निर्भरता। 4 पढ़िए

अनुच्छेद 11.8 के साथ। 3 अपीलार्थी अपनी ओर से अपने मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। न ही प्रिया वार्ट मामले में निर्णय [प्रिया वार्ट बनाम। भारत संघ, (1995) 5 एस. सी. सी. 437] का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन है क्योंकि उक्त मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान और ब्याज से संबंधित है। जो भुगतान में देरी के मामले में देय होगा

क्षतिपूर्ति "।

124. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने दोहराया है कि एक बार वहन लागत स्वीकृत हो जाने के बाद, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि वहन लागत पर ब्याज दिया जाए। इसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय सरल ब्याज के आधार पर की जानी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वहन लागत पर चक्रवृद्धि ब्याज का अनुदान और वह भी 'कानून में परिवर्तन' की घटना की तारीख से

घटना ध्वनि तर्क पर आधारित है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसका उद्देश्य एक ऐसे पक्ष को पुनर्स्थापित करना है जो 'कानून में परिवर्तन' घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है और इसे अपनी मूल आर्थिक स्थिति में बहाल करना है जैसे कि ऐसी 'कानून में परिवर्तन' घटना नहीं हुई थी।

125. यह तर्क कि पी. पी. ए. में उस तारीख से चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है जब 'कानून में परिवर्तन' किया गया था।

घटना हुई थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

126. कानून की इस सुसंगत स्थिति और प्रतिस्थापन सिद्धांतों के अनुप्रयोग और दोनों के बीच संविदात्मक दायित्वों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए

पी. पी. ए. एस. में निहित पक्षों के अनुसार, हम यह नहीं पाते हैं कि लागत वहन के संबंध में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण हस्तक्षेप का कारण बनता है।

तथ्य की समवर्ती खोज

127. उपरोक्त मुद्दों के अलावा, इन सभी अपीलों में एक और आम धागा है। इनमें से कई अपीलों समवर्ती होती हैं।

केंद्रीय/राज्य विद्युत नियामक आयोगों और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

128. यह न्यायालय, एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामले में। एपीएमएल और ओआरएस। (उपर्युक्त), विद्युत अधिनियम, 2003 के वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, सी. ई. आर. सी., एस. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ऐसे निकाय हैं जिनमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।

129. उक्त मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 120. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि दो विशेषज्ञ निकायों यानी सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने परीक्षण के बाद समवर्ती रूप से आयोजन किया है।

अभिलेख पर सामग्री, कि एस. एच. आर. और जी. सी. वी. के कारकों पर विनियमों या वास्तविक, जो भी कम हो, के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ राज्य नियामक निकायों ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद संबंधित शुल्क विनियमों में एस. एच. आर. मानदंडों को निर्दिष्ट किया था। इसके अलावा, जहां तक जी. सी. वी. का संबंध है, सी. ई. ए. ने राय दी है कि एक गैर-पिट हेड स्टेशन के लिए 85,100 किलोकैलरी/किग्रा के मार्जिन को वैगन टॉप पर मापा जाने वाला जी. सी. वी. का नुकसान माना जा सकता है, जब तक कि कोयले को अंदर फेंका नहीं जाता है।

बॉयलर।

121. इस संबंध में, हम निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस न्यायालय का

सीमित वी। महाराष्ट्र राज्य [(2019) 3 एस. सी. सी. 352]

" 38. एम. ई. आर. सी. एक विशेषज्ञ निकाय है जिसे नियम बनाने का कर्तव्य और कार्य सौंपा गया है, जिसमें शर्तें और कार्य शामिल हैं।

शुल्क के निर्धारण के लिए शर्तें। न्यायालय ने, जबकि

न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऐसा कदम उठाया जा सकता है जहां प्रकट अनुचितता या मनमानेपन का मामला बनाया जाता है। इसी तरह, जहां विधायिका का प्रतिनिधि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने या उन कारकों को ध्यान में रखने में विफल रहा है जिन्हें यह अनिवार्य है कानून द्वारा विचार करने के लिए या बाहरी विचारों पर शुल्क के अपने निर्धारण को स्थापित करने के लिए, न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।

हालाँकि, यह न्यायालय के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है कि वह एक निर्णय के लिए अपने स्वयं के निर्धारण को प्रतिस्थापित करे जो एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा भौतिक परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद किया गया था।

39. एसोसिएशन में। औद्योगिक विद्युत उपयोगकर्ता बनाम। एपी का राज्य [एसोसिएशन। औद्योगिक विद्युत उपयोगकर्ता बनाम। ए. पी. राज्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 711] इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने

शुल्कों का निर्धारण और इस प्रकार रखा गया: (एस. सी. सी पी. 717, पैरा 11)

श्री वारोरा एनर्जी लिमिटेड। वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

" 11. हम उच्च न्यायालय [एस. भारत] से भी सहमत हैं।

कुमार बनाम. एपी राज्य, 2000 एससीसी ऑनलाइन एपी 565: (2000) 6 ए. एल. डी. 217] कि शुल्क निर्धारण के संबंध में किसी मामले में न्यायिक समीक्षा किसी अपीलीय प्राधिकरण की तरह नहीं होनी चाहिए।

के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए

संविधान। उच्च न्यायालय को केवल इस बात से संतुष्ट होना है कि आयोग ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है

और जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि उसका निर्णय मनमाना या अवैध या अधिनियम के विपरीत है, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। शुल्क तय करना और क्रॉस-सब्सिडी प्रदान करना। अनिवार्य रूप से नीति का मामला है और आम तौर पर एक अदालत नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से बचती है जब तक कि शक्ति

प्रयोग मनमाना या कानूनी रूप से बुरा है।

XXX XXX XXX

123. हाल ही में, विवेक नारायण शर्मा बनाम के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठा भारत संघ [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1] ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए और जब तक यह नहीं पाया जाता है कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित हैं या वे प्रत्यक्ष रूप से मनमाने और अवैध हैं, तब तक इस न्यायालय के लिए इसे प्रतिस्थापित करना उचित नहीं होगा।

विशेषज्ञ निकायों के साथ विचार "।

130. जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में संकेत दिया गया है, इस न्यायालय को तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना चाहिए जब तक कि वे विकृत, मनमाने और या तो अज्ञानता में या इसके विपरीत न हों।

वैधानिक प्रावधान।

V. निष्कर्ष

131. अपने उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, अब हम विचार करेंगे

अपीलों का स्वतंत्र रूप से।

2018 की सिविल अपील सं. 11095 और सिविल अपील सं. 11910 11911 2018 का

132. अपीलों के इन समूह में, जहां तक डी. एन. एच. सी. ओ. एम. की अपील का संबंध है, वे व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार, कोयले की गुणवत्ता पर एफ अधिसूचना और एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन की अनुमति देने वाले विद्वान ई. एल. के आदेश से व्यथित हैं।

[2023] 8 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ले जाने के संबंध में विद्वान एपीटीईएल के निष्कर्ष से व्यथित लागत।

135. जहां तक शेष दावों का संबंध है, जो सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. दोनों द्वारा समवर्ती रूप से अनुमत और अस्वीकृत हैं, इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, किसी भी मामले पर ध्यान नहीं देते हैं। विकृति, मनमानेपन और/या वैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन। इसलिए, जनरेटर और डी. एन. एच.-डिस्कॉम दोनों की अपीलें खारिज की जा सकती हैं।

2021 की सिविल अपील Nos.4628-4629

136. विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने केवल व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार के आधार पर जनरेटर के दावे की अनुमति दी। कोयले के परिवहन और वहन लागत पर।

137. उपरोक्त मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, उस संबंध में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। हम नहीं पाते हैं अपीलों में योग्यता। तदनुसार, अपील खारिज किए जाने योग्य हैं।

सिविल अपील सं। 12055-12056 2018 का

138. व्यस्त मौसम अधिभार, विकास का मुद्दा

ऊपर हम पहले ही अधिभार और बंदरगाह भीड़भाड़ अधिभार पर विचार कर चुके हैं। ये सभी शुल्क रेलवे बोर्ड के माध्यम से भारतीय रेलवे द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत हैं। इस प्रकार, ज्ञात ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष के साथ कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है कि वे 'कानून में परिवर्तन' की घटनाओं के बराबर होंगे।

139. जहाँ तक 'वन कर' लगाने का संबंध है, वही राज्य सरकार द्वारा वैधानिक प्रावधानों के तहत लगाया जाता है।

140. 'वहन लागत' के संबंध में मुद्दे पर भी हमने ऊपर चर्चा की है।

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [वी. आर. गवई, जे.]

141. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अपीलें हैं, तदनुसार, बर्खास्त किए जाने योग्य।

सिविल अपील सं। 2935-2936 2020 का

142. राज्य आयोग द्वारा दिए गए 'कानून में परिवर्तन' लाभों के अलावा, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा 'कोयला टर्मिनल अधिभार', 'छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकार' और 'छत्तीसगढ़ विकास उपकार' को भी 'कानून में परिवर्तन' कार्यक्रम माना गया।

143. 'कोयला टर्मिनल अधिभार' भारतीय रेलवे द्वारा कट-ऑफ तिथि के बाद लगाया गया था। इसी तरह, छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 जून 2015 की अधिसूचना, जो कि निश्चित रूप से कट-ऑफ तिथि के बाद है, के माध्यम से छत्तीसगढ़ समन्वय विकास एवं पर्यावरण उपकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत 'छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकार' और 'छत्तीसगढ़ विकास उपकार' की शुरुआत की। यहां तक कि संचालन अवधि के लिए सेवा कर पर 0.50 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर में परिवर्तन और संचालन अवधि के लिए सेवा कर पर 5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर में परिवर्तन, जिसे राज्य आयोग और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा समवर्ती रूप से प्रदान किया गया था, कट-ऑफ तिथि के बाद भारत संघ द्वारा अधिसूचित किया गया था।

144. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ये सभी अतिरिक्त कर या उपकर भारत सरकार के साधनों द्वारा लागू किए गए थे या

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। उसी के तहत जारी किया जाता है संबंधित कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि के प्रावधान। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे पी. पी. ए. एस. में परिभाषित 'कानून' शब्द के अर्थ के भीतर 'कानून' के बराबर होंगे। इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. के क्रम में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

145. इसलिए, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार, अपील खारिज किए जाने योग्य हैं।

2019 की सिविल अपील संख्या 3123 और 2019 की सिविल अपील No.5372

2019

146. वर्तमान मामले में, सी. ई. आर. सी. द्वारा दिए गए दावों के अलावा, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने निम्नलिखित दावों को भी मंजूरी दी:

एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन (कैप्टिव ब्लॉक को रद्द करना बनाम

(1)

टेपरिंग लिंकेज),

((ख)

व्यस्त मौसम अधिभार और विकासात्मक अधिभार, [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वहन लागत; और

(iii)

प्रीमियम मूल्य जोड़ें।

(iv)

147. जहाँ तक एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन के संबंध में मुद्दे का संबंध है, यह न्यायालय एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) के मामले में और अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) में भी और हाल ही में एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम. एपीएमएल और ओआरएस। (सुप्रा) ने माना है कि एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा। इस प्रकार, उस संबंध में निष्कर्ष कोई हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

148. जहाँ तक व्यस्त मौसम अधिभार और विकास की बात है

अधिभार का संबंध है, हम यहाँ पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह 'कानून में परिवर्तन' के बराबर कैसे होगा।

149. जहाँ तक 'प्रीमियम मूल्य में वृद्धि' का संबंध है, निर्विवाद रूप से, रद्द करने के कारण 'प्रीमियम पर वृद्धि' का भुगतान करना आवश्यक था।

150. जहाँ तक 'वहन लागत' के संबंध में मुद्दे का संबंध है, हम पहले ही पूर्वगामी पैराग्राफ में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार, उस निष्कर्ष पर भी कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

151. जहाँ तक सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा समवर्ती रूप से अनुमत और अस्वीकृत अन्य दावों का संबंध है, समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, हम इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

एक ही।

152. डिस्कॉम्स के साथ-साथ जनरेटिंग दोनों की अपील

इसलिए कंपनियों को बर्खास्त किया जा सकता है।

2019 की सिविल अपील संख्या 6641

153. यह अपील जी. के. ई. एल. द्वारा दायर की गई है, जो कुछ घटकों पर लाभों के समवर्ती इनकार से व्यथित है।

154. जैसा कि हम पहले ही ऊपर चर्चा कर चुके हैं, सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दावों को अस्वीकार करने के लिए दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, अपील खारिज की जा सकती है।

सिविल अपील सं। 5583-5584 2021 का

155. वर्तमान मामले में, लाभ निम्नलिखित पर दिया जाता है:

आधार:

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

एन. सी. डी. पी. में बदलाव के कारण घरेलू कोयले की कमी;

((i)

मौजूदा टेपरिंग लिंकेज के कारण प्रीमियम जोड़ें

((ख)

तीन साल;

((iii)

व्यस्त मौसम अधिभार

157. जहाँ तक व्यस्त मौसम अधिभार का संबंध है, तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों के अलावा, हम पहले ही कारण दे चुके हैं यहाँ ऊपर बताया गया है कि यह 'कानून में परिवर्तन' के बराबर कैसे होगा।

158. हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार, वे ही खारिज किए जाने योग्य हैं।

2021 की सिविल अपील संख्या 39

159. सी. ई. आर. सी. ने निम्नलिखित आधारों पर लाभ प्रदान किया है:

आई.

एन. सी. डी. पी. 2013 के कारण लिंकेज कोयले में कमी और

शक्ति नीति;

संशोधन के अनुसार कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन

ii.

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986;

व्यस्त मौसम अधिभार और विकास में वृद्धि

iii.

भारतीय रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन पर अधिभार;

और

अनुमत 'कानून में परिवर्तन' दावों पर लागत वहन करना।

iv.

160. सी. ई. आर. सी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा की गई है। इस प्रकार, अपील तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों से उत्पन्न होती है।

161. जहाँ तक एन. सी. डी. पी. 2013 के कारण 'कानून में परिवर्तन' घटना के लाभ के संबंध में पहले मुद्दे का संबंध है, वही इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर), अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) और एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामलों में पूरी तरह से शामिल है। एपीएमएल और ओआरएस। (ऊपर)।

162. जहाँ तक शक्ति नीति के कारण 'कानून में परिवर्तन' के लाभ का संबंध है, यह [2023] 8 एस. सी. आर. के निर्णय और आदेश द्वारा कवर किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2021 की सिविल अपील सं. 5684 के मामले में और सिविल अपील सं. 564 के मामले में इस न्यायालय की सम तिथि 677-678 2021 का 1.

163. अन्य घटक, अर्थात् कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन और भारतीय रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन पर व्यस्त मौसम अधिभार और विकास अधिभार में वृद्धि, हम पहले ही इसमें 'कानून में परिवर्तन' की घटनाओं के बराबर मान चुके हैं। हमने 'वहन लागत' के मुद्दे पर भी विचार किया है। इस प्रकार, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए। तदनुसार, अपील खारिज की जा सकती है।

2022 की सिविल अपील संख्या 5005 और 2022 की सिविल अपील संख्या 4089

2022

166. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह विवाद में नहीं है कि ई. एफ. सी. को जनरेटरों द्वारा आधार मूल्य, अन्य शुल्कों का भुगतान करते हुए भुगतान किया गया है और कोयले की डिलीवरी के समय वैधानिक शुल्क। इस प्रकार, उक्त निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

167. जहाँ तक 'वहन लागत' का संबंध है, हमने उपरोक्त मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। इसलिए उक्त मुद्दे पर भी कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

168. हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार, वे ही खारिज किए जाने योग्य हैं।

VI. एपिलॉग

169. फैसला देने से पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें वर्तमान बैच में कई अपीलें मिली हैं जो सामने आती हैं

इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो वैधानिक निकायों द्वारा प्राप्त तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष। हमने यह भी पाया है कि कुछ मामलों में,

10 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक अन्य V. अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड और अन्य
11 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम। अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और एक अन्य जीएमआर वारोरा एनर्जी लिमिटेड।

वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

अपीलें केवल उसी को दाखिल करने के लिए दायर की गई हैं। हम यह भी पाते हैं कि कुछ कार्यवाहियों में मुकदमेबाजी के कई दौर हुए हैं।

170. हाल ही में, यह न्यायालय, एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम के मामले में। एपीएमएल और ओआरएस। (उपर्युक्त) ने उल्लेख किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने का एक कारण यह था कि विद्युत बोर्डों का प्रदर्शन था

विभिन्न कारकों के कारण बिगड़ गया। विद्युत अधिनियम, 2003 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलेगा कि विद्युत अधिनियम के अधिनियमन के लिए मुख्य विशेषताओं में से एक उत्पादन को अलग करना और स्वतंत्र रूप से कैप्टिव उत्पादन की अनुमति देना था। उक्त निर्णय में, हमने एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में विद्वान महान्यायवादी का बयान दर्ज किया है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने के बाद, बिजली अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को काफी हद तक पूरा किया गया था। उन्होंने कहा था कि कम बिजली उत्पादन के परिणामस्वरूप पहले की तुलना में कहीं अधिक बिजली का उत्पादन हुआ था। विद्वान महान्यायवादी ने न्यायालय से विद्युत अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले नाजुक संतुलन को बाधित नहीं करने का आग्रह किया था, यानी कि बिजली के उत्पादक या जनरेटर, ताकि वे बिजली संयंत्र स्थापित कर सकें, लाभ के उचित अंतर और अपनी पूंजी पर उचित लाभ के हकदार हों, ताकि वे अधिक से अधिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित हों। साथ ही अंतिम उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करने की आवश्यकता है।

171. हालाँकि, हम पाते हैं कि इस स्थिति के बावजूद, मुकदमों के बाद मुकदमों को आगे बढ़ाया जाता है। यद्यपि सांविधिक समवर्ती आदेश

विशेषज्ञ निकायों को विकृत, मनमाना या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है, उन्हें चुनौती दी जाती है।

172. याचिका संख्या 8/एम. पी./2014 में पारित 16 मई 2019 के अपने फैसले और आदेश में सी. ई. आर. सी. की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो इस न्यायालय के समक्ष 2021 की सिविल अपील संख्या 39 में विचार के लिए आती हैं:

" (घ) कानून में इस तरह के बदलाव के लिए मुआवजे के लिए हर साल आयोग से संपर्क करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। तदनुसार, बाद की अवधि के लिए भी पी. पी. ए. के अनुसार अनुमत कानूनी घटनाओं में परिवर्तन के कारण मुआवजे के भुगतान के लिए ऊपर निर्धारित तंत्र को अपनाया जा सकता है।

173. 21 दिसंबर 2021 के अपने आदेश में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. की कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा, जो [2023] 8 एस. सी. आर. है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष 2022 की सिविल अपील No.2908 में राशन, इस प्रकार:

संसद की स्थायी समिति ने 'बिजली क्षेत्र में तनावग्रस्त/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां' शीर्षक से ऊर्जा पर अपनी रिपोर्ट (दिनांक 07.03.2018) में कानून क्षतिपूर्ति में परिवर्तन की वसूली में देरी के कारण उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय तनाव को पहचाना है और

इस प्रकार अनुशंसित है:

" इसलिए समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की सिफारिश करती है कि कानून में परिवर्तन की स्थिति से उत्पन्न आदेशों के संबंध में एकरूपता और एकरूपता होनी चाहिए। इसके लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए

नियामकों के आदेशों को उनके विचार और निर्णय के लिए ए. पी. टी. ई. एल./उच्च न्यायपालिका के पास ले जाने की स्थिति में डिस्कॉम द्वारा भुगतान किए जाने वाले नियामक बकाया का कुछ प्रतिशत "

रिपोर्ट में वितरण के दायित्व पर जोर दिया गया है

स्वीकृत कानून परिवर्तन का भुगतान करने के लिए कंपनियाँ

क्षतिपूर्ति भले ही नियामक आयोग के आदेशों को चुनौती दी गई हो। विद्युत मंत्रालय (एम. ओ. पी.) द्वारा सी. ई. आर. सी. को बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 107 के संदर्भ में जारी किए गए नीति निर्देश में शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कानून सुआवजे में परिवर्तन। इस न्यायाधिकरण ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम आर. ई. आर. सी. और अन्य, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 98 में अपने दिनांक 14.09.2019 के फैसले में इसकी वांछनीयता को मान्यता दी थी। यह ऐसी पृष्ठभूमि में है कि बिजली (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, एम. ओ. पी. द्वारा अधिसूचित

22.10.2021 , समय पर वसूली के लिए

कानून में परिवर्तन की घटनाओं के कारण सुआवजा तैयार किया गया है। एम. ओ. पी. ने दिनांक 09.11.2021 की अधिसूचना के माध्यम से "ईंधन और बिजली के स्वचालित रूप से गुजरने" पर नीतिगत निर्देश को सार्वजनिक किया।

बिजली की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क में खरीद लागत "यह स्वीकार करते हुए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली क्षेत्र को ए. आर. ओ. आर. ए. एनर्जी लिमिटेड को बनाए रखने में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े।

वी. केंद्रीय निर्वाचन आयोग (सी. ई. आर. सी.) [बी. आर. गवई, जे.]

मांग को पूरा करने के लिए सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति, सभी

बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागत की समय पर वसूली हो। इसमें उत्पादन कंपनियों द्वारा वितरण की जाने वाली लागत शामिल है।

कंपनियाँ।

इसके एकदम विपरीत, यह तथ्यात्मक कथा से देखा जाता है

ऐसी घटनाएँ जो इस अपील की ओर ले जाती हैं कि अपीलकर्ता (हरियाणा उपयोगिताएँ) विलंबकारी रणनीति अपना रहे हैं जो न केवल सार्वजनिक नीति को पराजित करती हैं, बल्कि अंत के बोझ को बढ़ाने से अवांछनीय गिरावट भी होती है-उपभोक्ताओं को वे वहन करने की बढ़ती लागत के कारण सेवा करने का दावा करते हैं।

स्वीकार करते हुए, कर और कर्तव्य आदेश के अनुपालन में

जनवरी 2018 में पहली बार कोयले के आई. पी. टी. के संबंध में। विवादित आदेश पारित होने के बाद कहा जाता है कि अपीलकर्ताओं ने भुगतान करके कुछ हद तक अनुपालन करना शुरू कर दिया है। यह प्रथम उत्तरदाता का मामला है कि अपीलकर्ताओं ने करों और शुल्कों सहित पिछले भुगतानों को रोक दिया है जो संबंधित वसूली के लिए इसकी पात्रता है।

विलंबित भुगतान खरीद ("एल. पी. एस.") की गणना पूर्व दायित्व के निर्वहन के बाद की जानी है। हम इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की रोक अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन है। 2 और 11.6। 9 पी. पी. ए. (पहले उद्धृत) जो खरीददार (हरियाणा उपयोगिताओं) को विवाद की परवाह किए बिना उठाए गए चालान का सम्मान करने और एकतरफा कटौती/भुगतान के खिलाफ एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशिष्ट अधिदेश देता है।

हम कोयले की कमी और संबंधित करों और शुल्कों के कारण मुआवजे से संबंधित बाध्यकारी आदेशों के कार्यान्वयन में देरी करने के लिए हरियाणा उपयोगिताओं के विलंबकारी आचरण को अंत के हित के लिए हानिकारक पाते हैं। चूंकि यह जनरेटर को भुगतान करने में देरी के लिए उपभोक्ताओं पर वृद्धिशील एल. पी. एस. का बोझ डालता है। वैधानिक नियामक और अपीलीय मंच (ओं) द्वारा इस विषय पर पहले की व्यवस्था को देखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे दृष्टिकोण की गंध आती है जो [2023] 8 एस. सी. आर. को निराश करने के लिए बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधायी आदेश, और मौजूदा राज्य नीति, वास्तव में

यह कानून के शासन का उल्लंघन करने वाली घोर अनुशासनहीनता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्दों को उधार लेना

सेबी बनाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2014) 5 एस. सी. सी. 429 "पारित आदेशों का पालन न करना।

हमारी न्यायिक प्रणाली की नींव को हिलाता है और

इसके प्रति लोगों का विश्वास और विश्वास बनाए रखें
न्यायपालिका में देश "।

[जोर दिया
गया]

174. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि स्थायी समिति ने भी

यदि नियामकों के आदेशों को विद्वान ए. पी. टी. ई. एल./उच्च न्यायपालिका के पास उनके विचार और निर्णय के लिए ले जाया जा रहा है, तो डिस्कॉम्स द्वारा भुगतान किया जाना है। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 107 के संदर्भ में बिजली मंत्रालय द्वारा सी. ई. आर. सी. को जारी 27 अगस्त 2018 के नीतिगत निर्देश का भी उल्लेख किया है, जिसमें उसने 'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने 22 अक्टूबर 2021 को एम. ओ. पी. द्वारा अधिसूचित बिजली (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 का भी उल्लेख किया है, जिसमें मुआवजे की समय पर वसूली का प्रावधान है। 'कानून में परिवर्तन' की घटनाओं का लेखा-जोखा। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने पाया कि हरियाणा उपयोगिताएँ विलंबकारी रणनीति अपना रही हैं, जो न केवल सार्वजनिक नीति को पराजित करती हैं, बल्कि अंतिम बोझ को बढ़ाने के अवांछनीय परिणाम भी हैं-वे उपभोक्ता जो बढ़ती 'वहन लागत' के कारण सेवा करने का दावा करते हैं। ए. पी. टी. ई. एल. ने आगे पाया

यह कि डिस्कॉम्स द्वारा करें और शुल्कों सहित पिछले भुगतानों को रोकना, पी. पी. ए. के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो विवाद की परवाह किए बिना, उठाए गए चालानों का सम्मान करने के लिए खरीदार पर एक विशिष्ट जनादेश देता है, और एकतरफा कटौती/स्थापना के खिलाफ एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाता है।

175. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह न्यायालय, उत्तर के मामले में

हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएनएचवीएनएल) और एक अन्य V.

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) [वी. आर. गवई, जे.]

अडानी पावर लिमिटेड और अन्य ने विशेष रूप से कहा है कि 'कानून में परिवर्तन' की घटनाएं उस तारीख से आनी होंगी जिस दिन राज्य के उपकरणों द्वारा नियम, आदेश, अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। इस निष्कर्ष के बावजूद, डिस्कॉम मुकदमेबाजी के बाद मुकदमेबाजी कर रहे हैं।

176. हम पाते हैं कि जब पी. पी. ए. स्वयं 'कानून में परिवर्तन' के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, तो अनुचित मुकदमेबाजी, जो न्यायालय का समय बर्बाद करती है और साथ ही अंतिम उपभोक्ता द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की अंतिम लागत में वृद्धि करती है, से बचा जाना चाहिए। अंततः, डिस्कॉम के साथ-साथ जनरेटरों की ओर से मुकदमेबाजी की भारी लागत अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की लागत में वृद्धि करती है।

177. हम आगे पाते हैं कि विद्युत नियामक आयोगों द्वारा बकाया राशि का गैर-परिमाणीकरण और समय से पहले भुगतान

178. अंततः, इन विलंबित भुगतान अधिभारों को अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की लागत में जोड़ा जाता है। इस प्रकार यह अंत है उपभोक्ता जो उत्पादकों को समय पर भुगतान नहीं करने के कारण अधिक शुल्क का भुगतान करने से पीड़ित हैं।

179. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत इस न्यायालय में अपील केवल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर ही स्वीकार्य है। इस प्रकार, इस न्यायालय में अपील केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही स्वीकार्य होगी। हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले ही देखा जा चुका है, उन मामलों में भी जहाँ सुविचारित समवर्ती आदेश पारित किए जाते हैं

विद्युत नियामक आयोगों और ए. पी. टी. ई. एल. को डिस्कॉम के साथ-साथ जनरेटरों द्वारा भी चुनौती दी जाती है। मुकदमेबाजी के लंबित होने के कारण, जो इस बैच के कुछ मामलों में 5 साल से अधिक समय से लंबित है, बकाया का भुगतान न करने पर डिस्कॉम द्वारा जनरेटरों को भारी वहन लागत का भुगतान करना होगा, जो बदले में अंतिम उपभोक्ता को दिया जाएगा। नतीजतन, यह अंतिम उपभोक्ता होगा जो पीड़ित होगा। हमारी राय है कि इस तरह के अनावश्यक और अनुचित मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

2 (2019) 5 एस. सी. सी. 325 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

180. एक स्पष्ट प्रश्न के लिए, डिस्कॉम्स के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से इस स्थिति को स्वीकार किया कि जिन कीमतों पर बिजली उपलब्ध है

'स्वतंत्र बिजली उत्पादकों' से खरीदी गई बिजली राज्य उत्पादन कंपनियों से खरीदी गई बिजली की तुलना में काफी कम है।

181. इसलिए हम विद्युत मंत्रालय (संक्षेप में "एमओपी") के माध्यम से भारत सरकार से एक तंत्र विकसित करने की अपील करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादन कंपनियों को डिस्कॉम्स द्वारा समय पर भुगतान, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं को भारी बहन लागत से बचा जा सकेगा।

182. भारत संघ, एमओपी के माध्यम से, अनावश्यक और अनुचित मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक तंत्र भी विकसित कर सकता है, जिसकी लागत भी अंतिम उपभोक्ता को दी जाती है। 183. फैसला देने से पहले हम श्री बलवीर सिंह द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्री वी. गिरि, श्री एम. जी. रामचंद्रन, श्री सी. ए. सुंदरम, श्री मनिंदर सिंह, श्री साजन पूवय्या और श्री निरंजन रेड्डी, विद्वान वरिष्ठ वकील, और श्री विश्व मुखर्जी, सुश्री पूर्वा सहगल, सुश्री अनुश्री वर्धन और सुश्री पूनम सेनगुप्ता, विद्वान वकील।

184. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे (सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)